News सिटी चीफ
वर्ष-15, अंक-225
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सुविचार

'हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो।'

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

सिटी चीफ

इंदौर, बुधवार 20 नवम्बर 2024

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

झारखंड चुनावः 38 सीटों में 12.71 फीसदी वोटिंग

मधुपुर में मतदान पदाधिकारी गिरफ्तार

झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू है। दूसरे चरण में 12 जिले की जिन 38 सीटों में बुधवार (20 नवंबर) को चुनाव है। उनमें से 10 सीटों पर त्रिकोणीय और 28 सीटों पर NDA और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। सीएम हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मारंडी सहित 528 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में रोटी-माटी और बेटी संकट में है। छ्रूरू और कांग्रेस की सरकार ने नौजवानों को रोजगार के नाम पर ठगा है। मां, बहन और बेटियों का मान-सम्मान सुरक्षित नहीं है। संसाधनों पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था भी चिंताजनक है। यह सामान्य चुनाव नहीं, बल्कि झारखंड बचाने का चुनाव है। जनता सरकार से नाराज है। वह खुद NDA और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट कर रही है। मेरी सबसे अपील है कि वोट जरूर डालें। NDA सरकार झारखंड की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलेगी। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ क्रमांक 111 में मतदान पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि उन पर झारखंड मुक्तिमोर्चा के पक्ष में वोटिंग कराने का आरोप है। देवघर से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वोटिंग के बीच पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। कहा, हमारे सारे मुद्दे जनता तक चले गए हैं। किसी भी कीमत में हम दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा पहली बार झारखंड में अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। धनवार विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। कहा, मतदान लोकतंत्र का महापर्व है। 5 साल में एक बार प्रदेश के भविष्य को बढ़ाने का अवसर मिलता है। इसलिए राज्य के बेहतर भविष्य के लिए मतदान करें। हेमंत सोरेन ने 5 साल नौजवानों को छला है। जो गड़बड़ी हुई हैं, उसकी जांच करवाई जाएगी। जामताड़ा के करमाटांड थाना क्षेत्र में निजकजरा मोड़ के पास जेएमएम कार्यकर्ताओं पर देर रात हमला हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धनबाद रेफर किया गया है। बताया गया कि डमिरया गांव निवासी रंजीत मंडल और बालो मंडल बूथ लिस्ट बांटकर लौट रहे थे, तभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया है। धनबाद विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने कहा, वोटर्स जिस तरह से वोट देने निकल रहे हैं, उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। झारखंड के दूसरे और अंतिम चरण में संताल परगना की 18 सीटें, उत्तरी छोटा नागपुर की 18 और दक्षिणी छोटानागपुर की 2 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके लिए 14 हजार 218 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुबह 5 बजे मॉक पोल हुआ और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। हालांकि, कुछ जगह ईवीएम में दिक्कत के चलते वोटिंग थोड़ा देर से शुरू हुई। 48 पोलिंग बूथ यूनिक बनाए गए हैं। जबकि, 239 बूथों का संचालन महिलाएं कर रही हैं। मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग से निगरानी कराई जा रही है।

सुबह 9 बजे तक 6.61% मतदान, फिल्मी सितारों ने डाला वोट

शिंदे बोले- हमें मिलेगी जीत

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज उठी है। महाराष्ट्र के 35 जिलों की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। बुधवार (20 नवंबर) सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई जो शाम 6 बजे तक चलेगी। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह नौ बजे तक 6.61% मतदान हुआ। 12.33% के साथ गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई वहीं ओस्मानाबाद में सबसे कम महज 4.89 वोट डाले गए। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में चुनाव हो रहे हैं। चुनावी नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। यह चुनाव राज्य के लिए बेहद खास है क्योंकि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई टूट के बाद पहली बार दोनों पार्टियों के अलग-अलग गुट मैदान में हैं। भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के लिए यह चुनाव लिटमस टेस्ट होगा। महाराष्ट्र में 158 पार्टियां चुनावी रण में ताल ठोक रही हैं। 6 बड़ी पार्टियां अलग-अलग गठबंधनों का हिस्सा बनकर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। शिवसेना और एनसीपी में बंटवारे ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। राज्य में कुल 8.35 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 4 करोड़ से अधिक महिला मतदाता हैं। 18 से 29 साल के युवा मतदाताओं की संख्या करीब 2 करोड़ है। बीजेपी के महासचि विनोद तावड़े ने कैश कांड पर कहा कि राहुल गांधी मुझपर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी इस बात के सबूत दें कि मेरे पास से 5 करोड़ रुपए मिले हैं। मालेगांव नागपुर मध्य और नासिक के कुछ मतदान केंद्रों पर EVM में तकनीकी खराबी होने की बात सामने आई। नागपुर मध्य में इस वजह से एक घंटे देरी से वोटिंग शुरू हुई। अभिनेता रितेश देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी की सरकार आएगी। मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है उससे मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने जा रही है। मेरे दो भाई चुनावी मैदान में है और दोनों ही जीतेंगे। एनसीपी शरद चंद्र पावर के नेता शरद पवार बुधवार को बारामती के एक बूथ पर वोट डालने पहुंचे। बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी अजित पवार के पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार चुनावी मैदान में है।अभिनेता राजकुमार राव ने मुंबई के बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। इस मौके पर कहा कि आज बेहद ही अहम दिन है। आज वोटिंग डे है। प्लीज सभी लोग जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करे। फिल्म निर्देशक कबीर खान ने मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डाला। नागपुर में अपना वोट डालने के बाद आरएएसएस के पूर्व सरकार्यवाहक सुरेश भैय्याजी जोशी ने कहा कि इस वोटिंग से यही अपेक्षा है कि लोग जागरूक होकर और सूझबूझ से मतदान करें। अपने संविधान के अधिकार का उपयोग करें। वहीं पैसे बांटने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है।

उपचुनाव 2024 वोटिंग: 49.40 लाख वोटर्स करेंगे 170 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला

16 सीटों पर 9 बजे तक 9.12% वोटिंग

देश के 5 राज्यों की 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर बुधवार (20 नवंबर) को उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। 49.40 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का उपयोग कर 170 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला करेंगे। सबसे ज्यादा क्क की 9 सीटों पर 90 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पंजाब की 4 सीटों पर 45 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। उपचुनाव भाजपा, कांग्रेस, सपा और AAP के लिए अपनी साख बनाए रखने के लिहाज से बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के मीरापुर ककरौली में वोटिंग के दौरान पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया है। यहां सपा ने प्रशासन पर भाजपा उम्मीदवार के लिए काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही सपा समर्थकों को वोटिंग से रोकने का आरोप लगाया है। पंजाब के गुरदासपुर की डेरा बाबा नानक सीट के एक बूथ पर कांग्रेस-क्क समर्थकों में वोटिंग को लेकर झड़प हुई है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। डेरा बाबा नानक से क्क उम्मीदवार गुरदीप सिंह रंधावा भी मौके पर पहुंचे। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और क्क उम्मीदवार गुरदीप सिंह रंधावा ने आमने-सामने एक-दूसरे पर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश में सपा ने आरोप लगाया है कि मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट के एक बूथ से उनके एक समर्थक को पुलिस उठाकर ले गई है। सपा के बूथ एजेंट्स को धमकाया जा रहा है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर चमनगंज इलाके में पुलिस और क्र ने लोगों को दौड़ाया। मुस्लिम बहुल इलाकों के वोटरों का आरोप है कि प्रशासन लोगों को डरा रही है ताकि वह वोटिंग करने न जा सकें। तेज प्रताप सिंह यादव ने अपना वोट डालने के बाद कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार के कार्यकाल में लोगों को परेशान किया गया और सभी विकास परियोजनाएं रोक दी गईं... मुझे उम्मीद है कि यहां की जनता सपा का साथ देगी। जहां भी पुलिस लोगों को बेवजह परेशान कर रही है, हमने सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। हमें उम्मीद है कि आज निष्पक्ष मतदान होगा और लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव के दौरान गाजियाबाद के एक बूथ पर अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करते वोटर्स।करहल विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव ने बुधवार की सुबह वोटिंग के लिए रवाना होने से पहले इटावा के सैफई स्थित एक मंदिर में पूजा-अर्चना की।पलक्कड़ के एक बूथ पर मॉक पोल में जुटे मतदानकर्मी। पलक्कड़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने राहुल ममकूटाथिल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि भाजपा ने संदीप वरियर को चुनावी मैदान में उतारा है।उत्तर प्रदेश में उपचुनाव शुरू होने से पहले मिर्जापुर के एक बूथ पर तैयारियों में जुटे मतदानकर्मी। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर विधानसभा सीट से भाजपा गठबंधन से अपना दल (सोनेलाल) की नेता अनुप्रिया पटेल, समाजवादी पार्टी (सपा) के रमेश चंद बिंद और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के मनीष त्रिपाठी मैदान में हैं। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले बूथ पर मॉक पोलिंग में जुटे मतदानकर्मी।यहां मुकाबला भाजपा उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल और कांग्रेस की कैंडिडेट अमृता वारिंग के बीच है। अमृता वारिंग पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की पत्नी हैं। वहीं AAP ने हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों को मैदान में उतारा है।

उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 90 उम्मीदवार विधानसभा के उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 34,35,974 मतदाता हैं। 18,46,846 पुरुष, 15,88,967 महिलाएं और 161 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पंजाब की 4 सीटों पर 45 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। 6.96 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट से 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। 194706 वोटर इनके भाग्य का फैसला करेंगे। नांदेड़ लोकसभा में 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां 4.80 लाख से ज्यादा वोटर हैं। केदारनाथ सीट से 6 उम्मीदार मैदान में हैं। 90 हजार से ज्यादा वोटर हैं। मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक थे। अखिलेश 2024 में कन्नौज सीट से लोकसभा का चुनाव जीते और सांसद बन गए। अखिलेश के सांसद बनने से करहल सीट खाली हो हो गई। अंबेडकरनगर की कटेहरी से लालजी वर्मा विधायक थे। अंबेडकर नगर से सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे। संभल से सांसदी का चुनाव जीतने के बाद सीट खाली हो गई। अलीगढ़ की खैर सीट से अनूप वाल्मीकि सांसद थे। हाथरस से सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई। गाजियाबाद की सदर सीट से अतुल गर्ग विधायक थे। गाजियाबाद से सांसदी का चुनाव जीतने के बाद सीट खाली हो गई। मुजफ्फरनगर की मीरापुर से चंदन चौहान विधायक थे। बिजनौर के सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई। प्रयागराज की फूलपुर सीट से प्रवीण पटेल विधायक थे। फूलपुर के सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई। मिर्जापुर की मझवा सीट से विनोद कुमार बिंद विधायक थे। भदोही से सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई। कानपुर की सीसामऊ से इरफान सोलंकी विधायक थे। इरफान सोलंकी को सात साल की जेल हुई तो सीट खाली हो गई। अब इस सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ेंगी।

नांदेड़- वसंतराव चव्हाण के निधन से खाली हुई सीट

महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण के निधन से खाली है। लोकसभा चुनाव के सिर्फ दो महीने बाद ही अगस्त, 2024 में उनका देहांत हो गया था। पार्टी ने उनके बेटे रवींद्र चव्हाण को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने डॉ. संतुक हंबार्डे को उतारा है। पंजाब की चार सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। गिद्दड़बाहा से कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वडिंग विधायक थे। 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गए। इसलिए सीट खाली हो गई। डेरा बाबा नानक सीट विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा के सांसद बनने के बाद खाली हुई। चब्बेवाल सीट विधायक राजकुमार के सांसद बनने से खाली हो गई। बरनाला सीट गुरमीत सिंह के सांसद बनने से खाली हुई।

पलक्कड़ सीट इसलिए हुई खाली -पलक्कड़ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक शफी परम्बिल के वडकारा से सांसद चुने जाने से खाली हुई थी। कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल बीआर को और भाजपा ने अपने राज्य महासचिव सी कृष्णकुमार को टिकट दिया है। केदारनाथ विधानसभा सीट जुलाई 2024 में शैला रावत की मृत्यु के बाद खाली हुई थी। इस सीट से वो भाजपा की टिकट पर 2022 में चुनाव जीती थीं।

विदेश से मप्र में निवेश लाने के लिए सीएम यादव ब्रिटेन और जर्मनी जाएंगे

भोपाल। मध्यप्रदेश में विदेश से निवेश लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 24 से 30 नवंबर तक ब्रिटेन और जर्मनी प्रवास पर रहेंगे। उद्योग वर्ष 2025 में प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री यह छह दिवसीय विदेश यात्रा कर रहे हैं। वे ब्रिटेन के लंदन, बर्मिंघम तथा जर्मनी के म्यूनिख और स्टटगार्ट का दौरा करेंगे। इन स्थानों पर वे प्रदेश में निवेश और औद्योगिक सहयोग के अवसरों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 24 नवंबर को भोपाल से मुंबई होते हुए लंदन के लिए प्रस्थान करेंगे तथा रात 8 बजे लंदन पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री 25 नवंबर को वेस्टमिंस्टर स्थित ब्रिटिश संसद का दौरा करेंगे। वे किंग्स क्रॉस और पुनर्विकास स्थलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री लंदन में 'फ्रेंड्स ऑफ मध्यप्रदेश' प्रवासी भारतीयों द्वारा आयोजित रात्रि-भोज कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमे 400 से अधिक प्रवासी भारतीय सम्मिलित होंगे।

उद्योगतियों के साथ वन-टू-वन मीटिंग- मुख्यमंत्री 26 नवंबर को ब्रेकफास्ट पर उद्योगपतियों एवं भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोरईस्वामी से संवाद करेंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्यप्रदेश, इंटरैक्टिव सेशन में लगभग 120 प्रतिभागियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव लंच ब्रेक के बाद राउंड टेबल मीटिंग्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं ऑटो, एजुकेशन, रिन्युएबल एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में निवेश पर चर्चा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्योगतियों के साथ वन-टू-वन मीटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 27 नवंबर को वारविक यूनिवर्सिटी का भ्रमण करेंगे इसके बाद वारविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के डीन, फैकल्टी मेंबर्स और शोधार्थियों से संवाद करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव बर्मिंघम हवाई अड्डे से जर्मनी के लिए प्रस्थान कर रात 8:20 बजे म्यूनिख पहुंचेंगे।

28 और 29 नवंबर को जर्मनी प्रवास पर- मुख्यमंत्री डॉ. यादव 28 और 29 नवंबर को जर्मनी प्रवास पर रहेंगे। यात्रा के दौरान म्यूनिख और स्टटगार्ट में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 28 नवंबर को सुबह वे बवेरिया राज्य सरकार के नेताओं और म्यूनिख में कौंसुल जनरल ऑफ इंडिया से चर्चा करेंगे। इसके बाद डॉ. यादव एसएफसी एनर्जी का भ्रमण करेंगे। वे बेयरलोचर ग्रुप द्वारा आयोजित लंच में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्यप्रदेश, इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होंगे, जिसमें कौंसुल जनरल ऑफ इंडिया, सीआईआई और इन्वेस्ट इंडिया, इंडो जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इसमें लगभग 80 प्रतिनिधियों से मध्यप्रदेश में निवेश संबंधी चर्चा होगी। डॉ. यादव इन्टरैक्टिव सेशन के बाद उद्योग प्रतिनिधियों से वन-टू-वन मीटिंग में भी निवेश संबंधी चर्चा करेंगे।

थाना परिसरों में मंदिर निर्माण को लेकर सरकार ने पेश किया नहीं जवाब

हाईकोर्ट ने कॉस्ट लगाने की दी चेतावनी

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के थाना परिसरों में मंदिरों के निर्माण के मामले में सरकार की तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने सरकार को समय प्रदान करते हुए चेतावनी दी है कि जवाब पेश नहीं करने पर 25 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई जाएगी। युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निर्धारित की है। जबलपुर निवासी एडवोकेट ओपी यादव की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों में धार्मिक स्थलों के निर्माण पर प्रतिबंधित आदेश जारी किए थे। पुलिस थाने भी सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधित आदेश के बावजूद भी मध्यप्रदेश के कई थाने में मंदिरों का निर्माण करवाया गया है या करवाया जा रहा है। न्यायालयीन आदेशों को नजरअंदाज कर थाना परिसर के अंदर मंदिर निर्माण कराना सुप्रीम कोर्ट आदेशों का खुला उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की तरफ से जिले के चार थाना में किए गए मंदिर निर्माण की फोटो भी याचिका के साथ प्रस्तुत की गई थी। याचिका में राहत चाही गई थी कि थाना परिसर में बने सभी मंदिरों को तत्काल हटाया जाए। इसके अलावा संबंधित थाना प्रभारियों के खिलाफ सिविल सर्विस रूल्स के तहत कार्यवाही की जाए। याचिका में प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह विभाग, नगरीय प्रशासन, डीजीपी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जबलपुर सहित जिले के सिविल लाइंस, विजय नगर, मदन महल और लार्डगंज को अनावेदक बनाया गया था।

'द साबरमती रिपोर्ट' मप्र में टैक्स फ्री, सभी विधायक और सांसद देखेंगे फिल्म

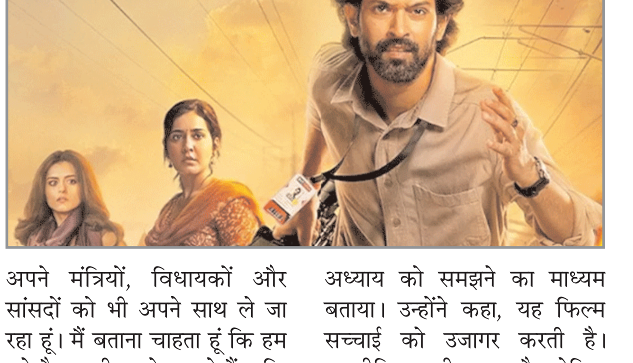

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है। मंगलवार को सीएम डॉ मोहन यादव ने एक सेमिनार में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि फिल्म साबरमती को एमपी के सभी विधायक और सांसद देखने जाएंगे। धीरज सरना द्वारा निर्देशित और विक्रांत मैसी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट ने अपने शुरुआती वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने की दुखद घटना पर आधारित इस फिल्म में रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना भी हैं। सीएम ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस फिल्म को देखने जा रहा हूं। मैं अपने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को भी अपने साथ ले जा रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हम इसे टैक्स फ्री करने जा रहे हैं ताकि अधिक लोग इसे देख सकें।

इतिहास के काले अध्याय को समझने का माध्यम- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की सराहना करते हुए इसे इतिहास के एक काले अध्याय को समझने का माध्यम बताया। उन्होंने कहा, यह फिल्म सच्चाई को उजागर करती है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन वोटों की राजनीति के लिए इतना गंदा खेल खेलना बेहद शर्मनाक था। सीएम यादव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने बेहद कुशलता और धैर्य से इस कठिन समय में गुजरात और देश की इज्जत बचाई।

गोधरा कांड की सच्चाई है इसमें- द साबरमती रिपोर्ट फिल्म के बारे में मध्यप्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह एक ऐसी फिल्म है, जिसने गोधरा कांड के बारे में सच्चाई पेश की है। इस फिल्म के जरिये वास्तविक तथ्यों को जनता के सामने स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। गोधरा कांड में 59 लोगों की जान चली गई थी। ट्रेन में आग लगा दी गई थी। इस घटना की पूरी सच्चाई इस फिल्म के माध्यम से सामने आती है। उन्होंने कहा कि यह अलग बात है कि उस समय कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने एक अलग कहानी बनाकर गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की थी, जो अब स्पष्ट हो चुका है। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस अक्सर बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने के लिए इतिहास को विकृत करती है।

फेक नैरेटिव ज्यादा दिनों तक नहीं चलता- गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फिल्म की तारीफ करते हुए कहा था कि फेक नैरेटिव ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। अच्छी बात है कि यह सच्चाई सामने आ रही है। द साबरमती रिपोर्ट साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना पर आधारित है। यह दुखद घटना 27 फरवरी, 2002 को हुई थी, जिसमें झुलस कर 59 लोगों की मौत हो गई थी।

'शौचालय डे' पर बिना शरमाए ली पब्लिक टॉयलेट के साथ सेल्फी

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार इंदौर में हमेशा नया प्रयोग होता है। शौचालय डे पर इंदौर में 700 टॉयलेट को अलग पहचान देने की कोशिश की गई। सुबह से रात तक एक लाख से अधिक लोगों ने टॉयलेट के साथ सेल्फी पोस्ट की। नगर निगम ने लोगों से अपील की थी कि पब्लिक टॉयलेट के साथ अपनी सेल्फी डाले। दरअसल, शौचालय डे पर इंदौर में पब्लिक टॉयलेट्स को दुल्हन की तरह सजाया गया। यह सारी कवायद पब्लिक टॉयलेट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने लेकर की गई। इसका मकसद भी कमाल का है। लोगों को पब्लिक टॉयलेट के बारे में जागरूक करना। यानी अब सार्वजनिक शौचालय में जाने में शर्म नहीं, बल्कि मजा आएगा। सोशल मीडिया पर 'सेल्फी विद शौचालय' ट्रेंड हो गया। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने पब्लिक टॉयलेट के साथ सेल्फी लेकर डाले और साफ-

स्वच्छ व सुलभ रहें, ताकि लोग इसके प्रति और ज्यादा जागरूक हो। साथ ही हमें यह भी पता चले की सफाई की कहां-कहां जरूरत है।

युवतियों ने किया जुंबा डांस

विजय नगर के पब्लिक टॉयलेट के बाहर मुख्य आयोजन रखा गया था। यहां लगे स्टेज पर युवतियों ने जुंबा डांस किया। रंगमंच से जुड़े कलाकारों ने स्वच्छता का संदेश देने वाले नुक्कड नाटक भी खेला। सुबह आठ बजे मेयर पुष्य मित्र भार्गव व विधायक रमेश मेंदोला पहुंचे। उन्होंने पब्लिक टॉयलेट के साथ सेल्फी ली। यहां के केयरटेकर का हार पहनाकर सम्मान भी किया गया। शहर के अन्य पब्लिक टॉयलेटों पर भी आयोजन हुए। शहर के पब्लिक टॉयलेट को सजाया गया और शहर के जनप्रतिनिधियों व शहरवासियों ने सेल्फी ली। उद्देश्य यह था कि शहरवासी पब्लिक टायलेट को भी साफ रखे। मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि लोग सफाई का और पर्सनल हाइजिन का ध्यान रखें। ओपन डिफेकेशन फ्री होने के बाद आज जब हम अष्ट सिद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज इंटरनेशनल टॉयलेट डे के अवसर पर इंदौर ने फिर पूरे भारत के सामने चुनौती रखी है। उन्होंने कहा कि आप अपने घर में कभी कोई गेस्ट आता है तो उसको आपकी टॉयलेट दिखते हो क्या? नहीं ,आप उन्हें घर में बेडरूम दिखते हो, ड्राइंग रूम दिखते हो, पूजा का घर दिखते हो, अपनी टॉयलेट तो हम घर में भी नहीं दिखाते हैं। उसके कई अलग कारण होंगे। इंदौर शहर है जो चुनौती देकर चैलेंज देकर कह रहा है कि आप इंदौर शहर की सीटीपीटी हमारी टॉयलेट के साथ सेल्फी लगाकर दिखाइए, इसलिए दिखाइए की इंदौर के पब्लिक टॉयलेट्स साफ है जो जन सुविधा जो पब्लिक को हम सुविधा देना चाहते हैं वैसी सुविधा उपलब्ध है। देश के सबसे साफ शहर इंदौर ने आठवीं बार स्वच्छता में सरताज बनने के लिए फिर से कमर कस ली है। स्वच्छता रैंकिंग सर्वेक्षण को देखते हुए शहर के 300 से ज्यादा पब्लिक टॉयलेट को नगर निगम ने साफ किया है और बिजली, पानी की सुविधा सुनिश्चित की है। इंदौर को जब पहली बार स्वच्छता रैंकिंग का पुरस्कार मिला था, तब इन पब्लिक टॉयलेटों के कारण भी इंदौर के नंबर बढ़े थे। इंदौर में पब्लिक टॉयलेटों पर विकलांगों के लिए रैम्प भी बनाए गए हैं।

2001 में हुई थी शुरुआत

मानव स्वच्छता को ध्यान में रखकर 2001 में वर्ल्ड टॉयलेट डे को मनाने की शुरुआत की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में पर्सनल हाइजीन और स्वच्छता रखने से है। लोगों को टॉयलेट का उपयोग बताने उनके स्वास्थ्य को किसी भी करण से प्रभावित होने से बचाने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है।

चेहरा एक और नाम दो, फर्जी पर शारजाह से आया शख्स गिरफ्तार

कलाम कबाड़ी के पासपोर्ट से खुले चौंकाने वाले राज

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। शारजाह से दो दिन पहले इंदौर आए एक व्यक्ति को भारत का फर्जी पासपोर्ट रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इंदौर पुलिस डीसीपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि 17 नवंबर की रात एक उड़ान से शारजाह से इंदौर पहुंचे व्यक्ति के पास दो अलग-अलग भारतीय पासपोर्ट मिले हैं। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे की आगमन जांच चौकी पर तैनात अधिकारियों को शक होने पर इस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया गया। डीसीपी ने बताया कि एक पासपोर्ट में इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद कलाम कबाड़ी और दूसरे पासपोर्ट में मोहम्मद कलाम राइन के रूप में दर्ज है। दोनों पासपोर्ट में उसकी जन्मतिथि और अन्य विवरण भी अलग-अलग हैं। मीना ने बताया कि 35 से 40 साल के बीच की उम्र वाले आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। एसीपी आलोक कुमार शर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी बिहार का रहने वाला है। वह रोजगार के सिलसिले में संयुक्त अरब अमीरात गया था। पुलिस यह पता लगाने में लगी है कि उसके दो पासपोर्ट बने कैसे। जांच के दौरान आरोपी कलाम कबाड़ी से पासपोर्ट की मांग की गई। जांच में पासपोर्ट में उम्र में अंतर दिखाई दिया। इस दौरान उससे सवाल किया गया तो उसने कहा कि करेक्शन करवाया है। इसके बाद उसने मोबाइल में दूसरा पासपोर्ट दिखाया तो वह दूसरे नाम का दिखा। इस चक्कर में कलाम कबाड़ी फंस गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

इन धाराओं में केस दर्ज

एरोड्रम पुलिस ने योगेश सोनी की शिकायत पर मोहम्मद कलाम राइन पर गलत पासपोर्ट के साथ यात्रा करने के मामले में 318 बीएनएस में केस दर्ज किया है। योगेश सोनी ने 18 नवंबर को एक लेटर एरोड्रम पुलिस को सौंपा था। इस पत्र में उन्होंने बताया कि उनकी इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर ड्यूटी थी। 17 नवंबर को 11 बजकर 15 मिनट पर वह एराइवल चेक पोस्ट पर मौजूद थे। शारजाह से इंदौर आने वाली फ्लाइट के यात्री मोहम्मद कलाम राइन को चेक किया। मोहम्मद कलाम कबाड़ी पुत्र मोहम्मद दाउद कबाड़ी द्वारा फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर यात्रा की गई। पासपोर्ट पर अंकित जन्म दिनांक और उनकी उम्र में अंतर दिखा। पत्नी और मां का नाम भी अलग पूछताछ के लिए ड्यूटी आफिसर दीपक मंडलोई ,विंग इंचार्ज सचिन गौतम को वहां बुलाया गया। मोहम्मद कलाम ने बताया कि उसने अपनी जन्म तिथि 1 जनवरी 1982 की जगह 1 जनवरी 1988 करवाई है। जो उन्होंने एक एजेंट के माध्यम से चेंज कराई है। इसके बाद मोहम्मद कलाम द्वारा मोबाइल में पुराना पासपोर्ट दिखाया गया। जिसमें पत्नी और मां का नाम भी अलग था। इसके बाद उसे कार्रवाई के लिए एअरपोर्ट पर रोका गया। बाद में पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।

ये दो पासपोर्ट मिले

मोहम्मद कलाम राइन के पासपोर्ट नंबर एन9592760 में मोहम्मद कलाम कबाड़ी के साथ जन्म दिनांक 1 जनवरी 1982 अंकित थी। जिसमें पिता का नाम मोहम्मद दाउद कबाड़ी, मां का नाम सबीला खातून और पत्नी का नाम जाहिदा खातून था। जबकि मोबाइल में मिले पासपोर्ट नंबर सी1661240 में जन्म दिनांक 1 जनवरी 1988 के साथ खुद का नाम मोहम्मद कलाम राइन पिता दाउद राइन, मां हसीना खातून और पत्नी जाहिरा खातून अंकित किया गया था।

दिनभर छाया कोहरा, दिन का तापमान गिरा, बारिश की भी संभावना

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। मध्यप्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और उत्तरी हवाओं के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। इंदौर में मंगलवार को सुबह से छाया कोहरा दिनभर छाया रहा। दिनभर ठंडी हवा बहती रही। मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में दिन का तापमान भी औसतन 2 डिग्री सेल्सियस कम है, जबकि रात के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राजधानी भोपाल में तापमान 13.2 डिग्री, जबलपुर में 12.6 डिग्री, उज्जैन में 15 डिग्री, इंदौर में 15.7 डिग्री और ग्वालियर में 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड से बचाव के लिए लोगों को गर्म कपड़े पहनने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। रात का तापमान सामान्य से नीचे इस समय राज्य के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, जहां तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भोपाल,

जबलपुर और उज्जैन जैसे प्रमुख शहरों में भी रात का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण ठंड का असर और बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी के साथ जेट स्ट्रीम हवाओं के प्रभाव से मध्यप्रदेश में ठिठुरन बढ़ रही है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है।

महीने के अंत में बरसेंगे बादल

प्रदेश में ठंड बढ़ने के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में स्कूलों की टाइमिंग को आधे घंटे आगे बढ़ा दिया गया है। पचमढ़ी के अलावा शहडोल, बालाघाट, शाजापुर, उमरिया, नौगांव, रीवा, छिंदवाड़ा, बैतूल, राजगढ़, रायसेन, खंडवा, खरगोन और सिवनी जैसे शहरों में भी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। ग्वालियर-चंबल संभाग में ठंड और बढ़ने की संभावना है, जहां सर्द हवाओं के साथ-साथ महीने के अंत में बारिश की भी उम्मीद जताई जा रही है।

टूटते परिवारो पर व्यख्यान 29 नवम्बर 2024 को

इंदौर । परिवार ही सबसे पहले गढ़ता है न आपके स्वभाव को ? परिवार ही देता है न सबसे पहले दिशा आपके जीवन को ? परिवार ही न देता है अपनापन सबसे पहले आपको ? जो परिवार हमारे जीवन की सफलता का सारथी है क्या उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य है ? मेरी भी इच्छा है मेरे घर में गार्गी, गौतमी, मैत्रेयी, कल्पना चावला और लक्ष्मी बाई जैसी बेटी हो। मेरी भी इच्छा है मेरे घर में सरदार पटेल, अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस और चंद्र शेखर आजाद जैसे बेटे हो। क्या मेरे परिवार का परिवेश वैसा है जिस पर मैं निश्चित हु कि एक दिन मेरे घर से भी कोई बछेंद्री पाल निकलेगी अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान बनेगी ? यह सब उदाहरण मात्र है हमारी परिवार व्यवस्था की रचना के प्रति समाज की संवेदनशीलता का। हम जैसा देश और समाज चाहते है उसके लिए हमारा पुरुषार्थ भी चाहिए वैसा ही। चलिए, हमारी सामुहिक जिम्मेदारी का अनुभव करें; कुछ साथ में विचार करें! भारत को

भारत बनाने की प्रक्रिया में सहभागी बनेंगे दिनांक 29.11.2024 , शुक्रवार को शाम 6.30 बजे लता मंगेशकर सभागृह, नर्मदा चौराहा राजेंद्र नगर पर। यह मात्र आमंत्रण नहीं साथ साथ खड़े होने और साथ साथ विचार कर सामूहिक जिम्मेदारी को वहन करने का आग्रह है।

तुम्हें मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा... अब पति-पत्नी नहीं कह सकते ऐसा

इंदौर। पति और पत्नी का रिश्ता काफी गहरा होता है. दोनों सात जन्मों तक साथ रहने का वचन लेते हैं। इस रिश्ते में काफी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कभी पत्नी को अपनी जिंदगी के फैसले बदलने पड़ते हैं तो कभी पति को, लेकिन ये बदलाव मर्जी के साथ होना चाहिए। इंदौर हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पति-पत्नी अपने पार्टनर से मन के मुताबिक जबरदस्ती रहने को नहीं का सकते। यह क्रूरता है। इंदौर के पारिवारिक कोर्ट में एक मामला दर्ज करवाया गया था। इसमें पत्नी ने अपने पति पर उसे जॉब न करने देने के लिए दवाब डालने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि उसे जॉब न करने देने के लिए, उसका पति बल का प्रयोग भी करता था। उसे मारता-पीटता भी था।

युवती के बर्थडे में जमकर मारपीट, विवाद ने सांप्रदायिक रूप लिया

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जिसमें दो पक्षों के बीच मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। यह घटना रात के समय शुरू हुई, जब परिवहन नगर क्षेत्र में खुशी नाम की युवती के घर बर्थडे पार्टी चल रही थी। वहां जोरदार शोर-शराबे की शिकायत पर किशन राठौर नामक व्यक्ति ने युवकों को शांत रहने के लिए कहा। किशन का आरोप है कि इस पर रिजवान, रेहान, अमान, शिब्बू और अम्जा ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ मारपीट की और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। वहीं, दूसरे पक्ष से रेहान शाह ने शिकायत दर्ज कराई कि खुशी उनकी दोस्त है और बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लोग घर के बाहर आकर गाली-गलौज करने लगे। इन लोगों ने उन पर कुर्सी से हमला किया और मारपीट कर उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। रेहान का कहना है कि उन्हें अपनी गाड़ियां छोड़कर वहां से भागना पड़ा। इस घटना के बाद रहवासियों ने चंदन नगर के युवकों पर चाकू से हमले और गाड़ियों में तोड़फोड़ के आरोप लगाए। उनका यह भी कहना है कि खुशी द्वारा डांस क्लास चलाने के कारण वहां अक्सर हुड़दंग होता है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विवाद की सूचना पर पुलिस देर रात मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। थाने में मामला पहुंचने के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर लिया है। यह मामला बर्थडे पार्टी से शुरू हुआ, लेकिन इसमें सांप्रदायिक तनाव की झलक भी देखने को मिली।

फसल हो रही चौपट, किसानों ने की नीलगाय को मारने की इजाजत देने की मांग

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। जिले में किसानों ने नीलगाय के बढ़ते आतंक के खिलाफ आवाज उठाई है। किसानों का कहना है कि नीलगाय उनकी फसलों को बर्बाद कर रही हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें नीलगाय को मारने की इजाजत दी जाए। वहीं पशु प्रेमियों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि नीलगाय को खेतों से दूर रखने के लिए दूसरे तरीके अपनाने चाहिए। दरअसल, इंदौर और आसपास के इलाकों में किसान नीलगाय के बड़े-बड़े झुंडों से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि नीलगाय गेहूं, चना, आलू, मटर, लहसुन, प्याज समेत तमाम फसलों को नष्ट कर रही हैं। भारतीय किसान मजदूर सेना के अध्यक्ष बबलू जाधव ने बताया कि इंदौर और पश्चिमी मध्यप्रदेश के दूसरे जिलों के किसान नीलगायों से बुरी तरह

परेशान हैं। इस जानवर के बेलगाम झुंड गेहूं, चने, आलू ,मटर, लहसुन, प्याज और दूसरी फसलों को किसानों की आंखों के सामने हर रोज बर्बाद कर रहे हैं। इस स्थिति में किसान बेबस हैं।

अगर नहीं दी परमिशन तो होगा आंदोलन

भारतीय किसान मजदूर सेना का कहना है कि राज्य सरकार को किसानों को नीलगायों को मारने की अनुमति देनी चाहिए ताकि वे अपनी फसलों की रक्षा कर सकें। किसानों का कहना है कि नीलगाय के डर से उन्हें रात भर जागकर खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। किसान नेता रामस्वरूप मंत्री ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि, इंदौर के वन मंडलाधिकारी एमएस सोलंकी का कहना है कि उन्हें अब तक इस बारे में किसानों की तरफ से कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर वे इसे भोपाल मुख्यालय को भेजकर आगे की कार्रवाई करेंगे।

पशु प्रेमी कर रहे विरोध

दूसरी तरफ पशु प्रेमियों ने नीलगाय को मारने की मांग का विरोध किया है। पीपुल फॉर एनिमल्स की प्रियांशु जैन का कहना है कि जंगलों का दायरा दिनों-दिन सिमटने के कारण नीलगायें इंसानी बस्तियों का रुख कर रही हैं। ऐसे में नीलगायों को मारा जाना या उन्हें कोई चोट पहुंचाया जाना सरासर गलत होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि किसान नीलगाय को खेतों से दूर रखने के लिए तेज आवाज में संगीत बजा सकते हैं या पटाखे फोड़ सकते हैं।

रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, भोपाल मंडल से गुजरने वाली 20 ट्रेनें निरस्त

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। रेल यात्रियों को एक बार फिर से परेशानी पढ़ने जा रही है दरअसल भोपाल मंडल से गुजरने वाली 20 गाड़ियों को निरस्त किया गया है। जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मण्डल के नौरोजाबाद स्टेशन पर तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री-नॉन/नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा है। इसी वजह से भोपाल मंडल से गुजरने वाली गाड़ियों को कुछ समय के लिए निरस्त की गई हैं। यदि आप भी ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो पहले कैंसिल ट्रेंनों की लिस्ट देख लें।

ये गाड़िया रहेंगी निरस्त
-23 नवम्बर से 02 दिसम्बर 2024 तक भोपाल से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

-21 से 30 नवम्बर 2024 तक बिलासपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

-23 से 30 नवम्बर 2024 तक जबलपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 11265 जबलपुर-अम्बिकापुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

- 24 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2024 तक अम्बिकापुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 11266 अम्बिकापुर-जबलपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

-22 से 30 नवम्बर 2024 तक बिलासपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18247 बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

-23 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2024 तक रीवा से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18248 रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

-25, 27 एवं 29 नवम्बर 2024 को रीवा से रवाना होने वाली गाडी संख्या 11751 रीवा-चिरमिरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

-26, 28 एवं 30 नवम्बर 2024 को चिरमिरी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 11752 चिरमिरी-रीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

-23 से 30 नवम्बर 2024 तक कटनी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 06617 कटनी-चिरमिरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 24 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2024 तक चिरमिरी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 06618 चिरमिरी-कटनी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 23 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2024 तक इंदौर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18233 इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 22 से 30 नवम्बर 2024 तक बिलासपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18234 बिलासपुर-इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

-25 एवं 28 नवम्बर 2024 को लखनऊ से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12535 लखनऊ-रायपुर गरीबरथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 26 एवं 29 नवम्बर 2024 को रायपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12536 रायपुर-लखनऊ गरीबरथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

-26 एवं 29 नवम्बर 2024 को दुर्ग से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22867 दुर्ग-नजमुद्दीन एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

-27 एवं 30 नवम्बर 2024 को निजामुद्दीन से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22868 निजामुद्दीन-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

-24 एवं 26 नवम्बर 2024 को दुर्ग से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18203 दुर्ग-कानपूर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

- 25 एवं 27 नवम्बर 2024 को कानपूर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18204 कानपूर-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 24 नवम्बर 2024 को दुर्ग से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18213 दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

-25 नवम्बर 2024 को अजमेर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18214 अजमेर-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

इन गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित
-गाड़ी संख्या 15231 बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस दिनांक 23 से 29 नवम्बर 2024 तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया कटनी-जबलपुर-नैनपुर-बालाघाट होते हुए गंतव्य को जाएगी।

-गाड़ी संख्या 15232 गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस दिनांक 23 से 29 नवम्बर 2024 तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया बालाघाट-नैनपुर-जबलपुर-कटनी होते हुए गंतव्य को जाएगी।

एमपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी जोरों पर, पेपर तैयार करवाने का काम शुरू

नकलचियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पेपर तैयार करवाने का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आधा से ज्यादा काम पूरा कर लिया है। वहीं परीक्षाओं के दौरान नकलचियों को पकड़ने के लिए विशेष व्यावस्था की जा रही है। अनुमान है कि इस बार करीब 18 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षाओं में शामिल होंगे। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार नवंबर अंत तक इन दोनों कक्षाओं के सभी विषयों पेपर तैयार हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट के 4-4 सेट बनेंगे। सभी का पेटर्न इस बार पूरी तरह से अलग रहेगा क्योंकि सभी सेट में प्रश्न तो एक जैसे ही रहेंगे लेकिन नकल ना हो इसके लिए इनका सीक्रेंस बिल्कुल अलग-अलग रहेगा। इस बार भी एमपी बोर्ड के मॉडल पेपर तैयार करेगा और मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट अपलोड किया जाएगा। इन पेपरों की मदद से बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले पेपरों का पेटर्न समझने में आसानी होगी।

मोबाइल फोन के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र पर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह नियम केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित सभी स्टाफ पर लागू किया जाता है। इस दौरान अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है। तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अपराधी को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुमार्ना भी भरना पड़ सकता है।

इसके साथ ही इस बार परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। जिसका चयन कलेक्टर करेंगे। इस बार परीक्षा का आयोजन साधन संपन्न स्कूलों में ही किया जाएगा। दरअसल, पिछले वर्ष कुछ जिलों में पेपर लीक सहित कई तरह की शिकायत मिली थी। जिसको देखते हुए कलेक्टर द्वारा यह फैसला लिया गया है। बता दें कि इस साल 18 लाख विद्यार्थी एमपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। जिसके लिए राज्य में चार हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे।

सभी सेट में एक जैसे ही रहेंगे प्रश्न
एमपी बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार हर सब्जेक्ट के 4-4 सेट बनेंगे। सभी का पेटर्न इस बार पूरी तरह से अलग रहेगा क्योंकि सभी सेट में प्रश्न तो एक जैसे ही रहेंगे लेकिन नकल ना हो इसके लिए इनका सीक्रेंस बिल्कुल अलग-अलग रहेगा।खास बात ये भी है कि इस बार भी एमपी बोर्ड के मॉडल पेपर तैयार करेगा ।

बताया जा रहा है कि पेपर तैयार करने के लिए प्रदेश के लगभग 650 शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पेपर की गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए पेपर कक्ष में संबंधित शिक्षक अपने साथ पेन, कागज, कॉपी, मोबाइल व इलेक्ट्रिक डिवाइस सहित अन्य कोई भी दस्तावेज नहीं ले जा सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे से शिक्षकों पर नजर रखी जा रही है।

मप्र सरकार ने तय की एमएसपी, 2 दिसंबर से धान की खरीदी होगी शुरू

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। धान की खरीद 2 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि ज्वार और बाजरे की खरीद 22 नवंबर से ही शुरू हो जाएगी। सरकार ने पूरे राज्य में 1500 से ज्यादा उपार्जन केंद्र स्थापित किए हैं ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो। किसानों को धान के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। मालदंडी ज्वार के लिए 3421 रुपए और ज्वार हाइब्रिड के लिए 3371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बाजरे के लिए 2625 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। सरकार का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन धान, 3 लाख मीट्रिक टन बाजरा और 50 हजार मीट्रिक टन ज्वार की खरीद करना है।

धान की खरीद के लिए सबसे ज्यादा 185 उपार्जन केंद्र बालाघाट जिले में बनाए गए हैं। सतना में 144, जबलपुर में 125 और रीवा में 123 केंद्र बनाए गए हैं। ज्वार और बाजरे की खरीद के लिए सबसे ज्यादा 51 उपार्जन केंद्र मुरैना जिले में स्थापित किए गए हैं। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी उपज की गुणवत्ता का ध्यान रखें। उपज की गुणवत्ता की जांच सर्वेयर द्वारा की जाएगी। परिवहन और भंडारण में देरी करने पर जुमार्ना लगाया जा सकता है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान उनके पंजीकृत बैंक खातों में किया जाएगा। इसके लिए आधार लिंक होना अनिवार्य है। पंजीयन, उपार्जन और भुगतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान 0755-2551471 पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कार्यरत रहेगा।

स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर भर्ती में देरी पर डिप्टी सीएम हुए नाराज

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। मध्यप्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य स्टॉफ की कमी पूरी करने के लिए भर्ती की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में विभाग देरी की जा रही है। इसे लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जीएडी और विभाग के आला अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने असंतोष जताया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों की बैठक में इस बारे में साफ कहा कि विभागों में कोआर्डिनेशन बना रहना चाहिए। संजीवनी क्लीनिक में पद रिक्त हैं और नए जिलों में जिला अस्पतालों में रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है, इसके लिए पीएससी को प्रस्ताव भेजने के काम में तेजी लाने के लिए कहा। अधिकारियों की बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं। राज्य सरकार प्रदेश को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर सुधार के लिए अंतर्विभागीय समन्वय आवश्यक है ताकि तेज गति से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा सके। मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों और अंतर्विभागीय समन्वय विषयों की समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग संजय दुबे, प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव और आयुक्त स्वास्थ्य तरुण राठी की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने संजीवनी क्लीनिक में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्तियां करने के निर्देश दिए। इस दौरान शुक्ला ने कहा कि प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं को सशक्त करने के लिए प्रक्रिया को तेज गति से पूरा किया जाए। नए जिलों में जिला चिकित्सालयों के लिए चिकित्सकीय और पैरामेडिकल पदों की पूर्ति की प्रक्रिया की अपडेट स्थिति की समीक्षा के दौरान शुक्ल ने निर्देश दिए कि सभी आवश्यक प्रस्ताव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को शीघ्र भेजे जाएं ताकि रिक्त पद जल्द भरे जा सकें और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो सके। शासकीय मेडिकल कॉलेजों में पे-प्रोटेक्शन के विषय पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में आईपीएचएस मानक के अनुसार रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।

किराएदारों की डिटेल न दे पाने पर मकान मालिकों पर एक्शन शुरू

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। राजधानी पुलिस ने किराएदारों का अनिवार्य वेरिफिरेशन न करने पर दो मकान मालिकों के खिलाफ एक्शन लिया है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने ऐसे आदेश जारी किए थे। इसके बाद अयोध्या नगर पुलिस ने दो मकान मालिकों के खिलाफ अनिवार्य किरायेदारों का वेरिफिकेशन न दे पाने पर धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज की है। मकान मालिक, जिनकी पहचान हरिसिंह यादव और मनोज कुमार गुप्ता के रूप में की गई है, दोनों अयोध्या नगर के एन-सेक्टर के निवासी हैं, नियमित गश्त और जांच के दौरान निर्देश का उल्लंघन करते पाए गए। पुलिस के इस एक्शन से इलाके में हड़कंप मच गया। एसएचओ अयोध्या नगर महेश लिल्हारे ने कहा कि कमिश्नर ने मकान मालिकों और संस्थानों को किरायेदार और कर्मचारी की जानकारी पुलिस पोर्टल पर अपडेट करने या संबंधित पुलिस स्टेशनों में जमा करने का आदेश दिया है। पुलिस स्टेशनों और मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित निर्देश का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बढ़ते अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा के लिहाज से ऐसे आदेश पुलिस कमिश्नर ने जारी किए थे। एसएचओ लिल्हारे ने कहा कि निरीक्षण के दौरान पता चला कि मकान मालिक हरिसिंह यादव और मनोज कुमार गुप्ता अपने किरायेदारों की डिटेल पुलिस को रिपोर्ट करने या पोर्टल पर अपडेट करने में विफल रहे। यह धारा 223 बीएनएसएस के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप, कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गईं और जांच चल रही है।

भाजयुमो नेता पर दुष्कर्म का केस दर्ज, पद से इस्तीफा

भोपाल। बालाघाट जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे पर शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं, इस घटना पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एफआईआर की कॉपी ही अपलोड कर पीड़िता की पहचान उजागर कर दी, जिससे उन पर पीड़िता की पहचान उजागर करने के सवाल उठ रहे हैं। भाजयुमो नेता भूपेंद्र सोहागपुरे ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने लिखा कि मेरे ऊपर एक महिला ने फर्जी मामला बनाया है। मेरी वजह से संगठन की छवि खराब न हो, इसलिए जब तक मैं न्यायालय से न्याय प्राप्त न कर लूं, अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। वहीं, इस मामले पर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पार्टी के भीतर ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस विवाद को और बढ़ाते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एफआईआर की कॉपी साझा की, जिसमें पीड़िता का नाम और जाति का उल्लेख किया।

भोपाल में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में देरी पर निर्देश जारी

भोपाल। राजधानी भोपाल में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं हो पा रहा है। लगातार बढ़ रही पेंडिंग को लेकर कलेक्टर ने पिछले दिनों नाराजगी व्यक्त की थी अब एक बार फिर से सोमवार को संभाग आयुक्त संजीव सिंह और भोपाल कलेक्टर अलग-अलग समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों और समय-सीमा में प्राप्त पत्रों की समीक्षा कर उनके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें और प्राथमिकता के आधार पर सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।

राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा पेंडिंग
जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा शिकायतें पेंडिंग है इसे लेकर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की है। शिकायतों के समाधान में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर सिंह ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से बैरसिया तहसील में सीएम हेल्पलाइन और राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर जोर देने के निर्देश दिये। साथ ही नगर निगम, स्वास्थ्य, श्रम और सहकारिता विभाग में लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को संतोषजनक रूप से हल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत सभी राजस्व अधिकारियों को आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का समाधान कर भोपाल को प्रथम स्थान पर लाने की कोशिश करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कैंप और रणनीति बनाकर जनता के साथ संवाद स्थापित करते हुए अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्रों के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा करें। साथ ही पटाखों की दुकानों का निरीक्षण करें, गोदामों को शहर से बाहर उचित स्थान पर शिफ्ट करने, भूमि आवंटन, भूमि अधिग्रहण और धारणाधिकार प्रकरणों को समयबद्ध रूप से हल करने के निर्देश दिए। बरखेड़ी अब्दुला में प्रस्तावित अत्याधुनिक गौशाला निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर समय-सीमा में टेंडर जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत ऋतुराज सिंह, एडीएम भूपेन्द्र गोयल, अंकुर मेश्राम सहित सभी एडीएम, एसडीएम और जिला अधिकारी उपस्थित रहे। संभाग आयुक्त संजीव सिंह ने समीक्षा बैठक आयोजित कर सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की गहन समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समाधान त्वरित और गुणवत्ता पूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए। बैठक में संभाग के विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया गया। संभाग आयुक्त श्री सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर जोर देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों का निराकरण समय-सीमा में किया जाए।

सम्पादकीय

मणिपुर में बेमन से की गईं हिंसा रोकने की कोशिशें?

मणिपुर हिंसा सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। करीब 18 महीने से नगा-कुकी और मैतेई समुदाय आमने-सामने हैं और जातीय हिंसा में आगजनी, बवाल और हत्याओं का सिलसिला थमा नहीं है। आज भी वहां अराजकता बेलगाम और सरकार लाचार खड़ी दिखती है। आखिर क्या वजह है कि हर कुछ रोज बाद हिंसा की बड़ी घटनाएं एक तरह से सरकार के सामने चुनौती देती हुई लग रही हैं और उस पर काबू पाने में वहां का प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है।

मणिपुर हिंसा सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। करीब 18 महीने से नगा-कुकी और मैतेई समुदाय आमने-सामने हैं और जातीय हिंसा में आगजनी, बवाल और हत्याओं का सिलसिला थमा नहीं है। आज भी वहां अराजकता बेलगाम और सरकार लाचार खड़ी दिखती है। आखिर क्या वजह है कि हर कुछ रोज बाद हिंसा की बड़ी घटनाएं एक तरह से सरकार के सामने चुनौती देती हुई लग रही हैं और उस पर काबू पाने में वहां का प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। कुछ दिन पहले वहां गंभीर हिंसक घटनाओं का नया दौर फिर से शुरू हो गया है और आम लोगों की जान जा रही है। हाल ही में एक महिला की हत्या करके उसका घर जला दिया गया था। उसके बाद एक अन्य शिविर से छह लोग लापता हो गए। बाद में उनके शव मिलने की खबरें आईं। अब स्थानीय लोगों के बीच सरकार की इस व्यापक नाकामी के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है और इस तरह हिंसा का दायरा अब और फैलता जा रहा है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वहां कुछ लोगों ने अब विधायकों और मंत्रियों के घरों में आग लगाना शुरू कर दिया है। शनिवार और रविवार को कई विधायकों और मंत्रियों के घरों पर लोगों की भीड़ ने हमला किया, आग लगा दी और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। यह समझना मुश्किल नहीं है कि कुकी और मैतेई समुदायों के बीच लंबे समय से चल रही हिंसा के बाद अब लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ भड़क रहा है और नेता भी हमलों के निशाने बनने लगे हैं। निश्चित रूप से यह स्थिति किसी भी हाल में उचित नहीं मानी जा सकती, मगर ताजा हिंसा से यही लगता है कि इसमें शामिल दोनों समुदाय अब शायद इससे ऊब रहे हैं और उनका आक्रोश सरकार और राजनीतिक तबके के खिलाफ फूट रहा है। सवाल है कि किसी भी सरकार को अपना समूचा सुरक्षा तंत्र झोंकने के बाद हिंसक घटनाओं पर काबू पाने में कितना वक्त लगना चाहिए? पिछले वर्ष मई महीने में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने के सवाल पर दो समुदायों के बीच जिस हिंसक टकराव की शुरुआत हुई थी, उसमें अब तक सवा दो सौ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। राज्य सरकार की पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के साथ-साथ सेना तक ने वहां मोर्चा संभाला। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की ओर से शांति कायम करने के लिए कई स्तर पर कवायदें हुईं। मगर हालत यहां तक पहुंच गई है कि अराजकता पर काबू पाना तो दूर, अब मंत्री-विधायकों के घर भी हिंसा की आग का शिकार होने लगे हैं। कहने को शांति कायम करने के मकसद से दोनों पक्षों के बीच बातचीत की प्रक्रिया शुरू कराने का दावा कई बार किया गया, लेकिन आज भी वहां जिस तरह लोगों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, उसमें किसी की हत्या कर दी जा रही है, उससे साफ है कि सरकार की कोशिशें या तो बेमन से की गईं या फिर उसके पीछे कोई स्पष्ट दृष्टि और इच्छाशक्ति नहीं थी। हैरानी की बात यह है कि अब भी सरकार एक तरह से 'सब कुछ सामान्य होने' की मुद्रा में बेफिक्र दिख रही है। वरना क्या कारण है कि राज्य में गृह युद्ध की हालत लंबे वक्त से कायम है, लेकिन केंद्र की ओर से भी राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अब फिर सीआरपीएफ की पचास कंपनियां भेजने का फैसला किया गया है, मगर वहां की हिंसा अब जिस शक्ल में पहुंच गई लगती है, उसके लिए अब बहाने बनाने के बजाय तात्कालिक तौर पर हिंसा को रोक कर उसकी जड़ों को सुलझाने की जरूरत है। दरअसल, मणिपुर में मुख्य रूप से तीन समुदाय हैं। पहला- मैतेई, दूसरा- नगा और तीसरा- कुकी। इनमें नगा और कुकी आदिवासी समुदाय हैं। जबकि मैतेई गैर-आदिवासी हैं। मैतेई समुदाय की आबादी यहां 53 फीसदी से ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ घाटी में बस सकते हैं। वहीं, नगा और कुकी समुदाय की आबादी 40 फीसदी के आसपास है और वो पहाड़ी इलाकों में बसे हैं। मणिपुर में एक कानून है, जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं।

देश की पूरी आबादी को नहीं मिल रही शुद्ध हवा

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की दमघोटू हवा के लिए अगर जलती हुई पराली के धुएं को जिम्मेदार माना जाए तो भी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और बिहार से भी हवा के खतरनाक स्तर तक पहुंचने की पुष्टि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कर रहा है। मानकों के अनुसार वायु प्रदूषण सूचकांक (एक्यूआई) का 300 अंक पार कर जाने का मतलब हवा का बहुत खराब होना माना जाता है और इन दिनों देश के 88 से अधिक नगरों के निवासी इतनी खराब हवा में सांस ले रहे हैं। भारत की लगभग शत-प्रतिशत आबादी वायु प्रदूषण से प्रभावित है।

दिल्ली इन दिनों खतरनाक हो चुकी प्रदूषित वायु के कारण गैस चैम्बर के तौर पर प्रचारित हो रही है। देश की राजधानी की यह हालत निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। प्रदूषित हवा दिल्ली के अलावा भी कम से कम 6 राज्यों के दर्जनों शहरों का दम घोंट रही है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की दमघोटू हवा के लिए अगर जलती हुई पराली के धुएं को जिम्मेदार माना जाए तो भी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और बिहार से भी हवा के खतरनाक स्तर तक पहुंचने की पुष्टि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कर रहा है। मानकों के अनुसार वायु प्रदूषण सूचकांक (एक्यूआई) का 300 अंक पार कर जाने का मतलब हवा का बहुत खराब होना माना जाता है और इन दिनों देश के 88 से अधिक नगरों के निवासी इतनी खराब हवा में सांस ले रहे हैं। भारत की लगभग शत-प्रतिशत आबादी वायु प्रदूषण से प्रभावित है।

प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव का देश की आर्थिकी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वर्ष 2017 में प्रदूषणजन्य कैंसर, पक्षाधात और दिल की बीमारियों आदि से बड़ी संख्या में मौतों और श्रमशक्ति के क्षय के कारण देश को 30 से 78 बिलियन श्रम आय का नुकसान हुआ जो कि देश की जीडीपी के 0.3 से लेकर 0.9 प्रतिशत तक था। यही वजह है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु जैसा प्रभावशाली कार्यक्रम चलाया है।

लैंसेट पत्रिका द्वारा गठित लैसेंट कमीशन के एक नए अध्ययन के अनुसार प्रदूषण के कारण विश्व में 2019 में 90 लाख और भारत में 23 लाख से अधिक लोगों की असामयिक मृत्यु हुई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 17 लाख मौतें अकेले वायु प्रदूषण के कारण हुईं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष विश्व में 70 लाख लोगों की असामयिक मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार सांस लेने के लिए सबसे शुद्ध वायु शून्य से 50 अंक तक और सन्तोषजनक वायु 51 से लेकर 100 अंक के बीच मानी जाती है और 200 एक्यूआई से लेकर 300 तक खराब, 300 से लेकर 400 अंक तक बहुत खराब और 400 से लेकर 500 अंक तक वायु को खतरनाक (सीवियर) माना जाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सोमवार 6 नवम्बर को जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के अनुसार हरियाणा के फरीदाबाद के न्यू इंडस्ट्रियल टाउन की एक्यूआई 500 अंक तक पहुंच चुकी थी। उत्तर प्रदेश के लोनी की एक्यूआई 490 तक पहुंच गई। दिल्ली के राहिणी की एक्यूआई 476 अंक को छू गई। दिल्ली के अलावा देश के कई अन्य नगरों की हालत भी कम चिन्ताजनक नहीं है।

नवीनतम 6 नवम्बर को जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार बिहार के 7 शहरों का एक्यूआई इन दिनों 300 अंक पार कर रहा है। दिल्ली के 32 वायु प्रदूषण जांच केंद्रों ने 300 अंक से अधिक और 26 ने 400 अंक तक खराब गुणवत्ता दर्ज की है। इसी प्रकार हरियाणा के 20 नगरों के स्टेशनों ने 300 से अधिक और 4 ने 400 अंक से अधिक एक्यूआई दर्ज की है। मध्यप्रदेश में एक तथा महाराष्ट्र में 2 नगरों तथा राजस्थान के 6 नगरों की वायुगुणवत्ता 300 अंक से अधिक खराब दर्ज की गई,जबकि राजस्थान के ही भिवाड़ी में एक्यूआई 462 दर्ज की गई है। दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश की हालत भी चिन्ताजनक बनी हुई है। यहां 17 नगरों में एक्यूआई 300 और 6 में 400 पार गया है।

हवा जीवन के लिए अत्यन्त जरूरी है। भोजन के बिना मनुष्य कई दिनों तक जीवित रह सकता है, पानी के बिना भी कई-कई दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन हवा के बिना कोई कुछ मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। वायु केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं वरन् सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। अगर हवा ही जहरीली हो गई तो जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) हवा की समग्र गुणवत्ता का एक माप है। इसकी गणना पांच प्रमुख वायु प्रदूषकों की सांद्रता का उपयोग करके की जाती है। जमीनी स्तर पर ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5 और पीएम10), कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ग्राउंड-लेवल ओजोन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनता है।

यह स्मॉग का एक प्रमुख घटक है और श्वसन प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जमीनी स्तर पर ओजोन के निर्माण में योगदान करती है और श्वसन प्रणाली को हानि कर सकती है। प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड कोयला और तेल जैसे सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है। इससे श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन युक्त ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है। सीसे के अलावा, अन्य भारी धातुएं जैसे पारा, कैडमियम और आर्सेनिक औद्योगिक प्रक्रियाओं और दहन से हवा में छोड़े जा सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। अमोनिया गैस वायु की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

भारत में वायु प्रदूषण एक महत्वपूर्ण और जटिल समस्या है, और इसके समाधान के लिए सरकारी नीतियों, तकनीकी नवाचारों, सार्वजनिक जागरूकता और व्यक्तिगत कार्यों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत सरकार को वाहनों, उद्योगों और बिजली संयंत्रों के लिए और सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करने की आवश्यकता है। स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने से उत्सर्जन में काफी कमी आ सकती है।

वाहनों से प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) अपनाने को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) जैसे स्वच्छ ईंधन में निवेश करने से वाहन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना आवश्यक है।

सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने से बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है, जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। वनीकरण और शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने से वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण और खुले में अपशिष्ट जलाने को कम करने सहित प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने से हवा में हानिकारक प्रदूषकों को फैलने से रोका जा सकता है।

वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार और सुधार प्रदूषण के स्तर का आकलन करने, प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने और जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में सूचित करने में मदद कर सकता है। सार्वजनिक जागरूकता अभियान से नागरिकों को वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में सूचित किया जा सकता है।

कोचिंग सेंटरों की मनमानी रोकने की कवायद

आम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, खासकर कोचिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों और आम जनता को कोचिंग सेंटरों द्वारा भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं से बचाना है। बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की मुख्य आयुक्त और भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग की सचिव, निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई थी, जिसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, शिक्षा मंत्रालय, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली, विधि फर्म और उद्योग हितधारकों जैसे संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद समिति ने शिक्षा मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, एलन, फिटजी, कैरियर 360, सिविक इनोवेशन फाउंडेशन और कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर सहित 28 विभिन्न हितधारकों से सार्वजनिक सुझाव प्राप्त किए। इस समिति का लक्ष्य कोचिंगह्न जिसमें शैक्षणिक सहायता, शिक्षा प्रदान करना, मार्गदर्शन, निर्देश, अध्ययन कार्यक्रम या ट्यूशन या समान प्रकृति की कोई अन्य गतिविधि शामिल है, में सुधार लाना है। झूठे व भ्रामक दावों, अतिरंजित सफलता दरों और कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों पर अक्सर थोपे जाने वाले अनुचित अनुबंधों के बारे में बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर कोचिंग क्षेत्र में सुधार को लेकर समिति द्वारा दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इस तरह के विज्ञापनों में छात्रों को गुमराह करने, महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने, झूठी गारंटी देने आदि शामिल हैं। इसमें प्रस्तावित पाठ्यक्रम, उनकी अवधि, संकाय योग्यता, शुल्क और धन वापसी नीतियां भी शामिल की गईं। साथ ही चयन दरें, सफलता की कहानियां, परीक्षा रैंकिंग और नौकरी सुरक्षा के वायदों पर रोक की ठोस नीति बनाई गई है।

सुनिश्चित प्रवेश, उच्च परीक्षा अंक, गारंटीकृत चयन या पदोन्नति व गुणवत्ता या मानक के बारे में भ्रामक प्रस्तुतीकरण सख्त वर्जित किया गया है। कोचिंग संस्थानों को अपने बुनियादी ढांचे, संसाधनों और सुविधाओं का सही-सही विवरण सार्वजनिक करने के निर्देश भी इसमें शामिल है। इस बाबत दिशा-निर्देशों का कोई भी उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन माना जाएगा। केंद्रीय प्राधिकरण के पास अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की शक्ति निहित की गई है, जिसमें दंड लगाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों को रोकना शामिल है। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार शासित होंगे और दिशा-निर्देश हितधारकों के लिए स्पष्टता लाएंगे और उपभोक्ता हितों की रक्षा करेंगे। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन पर लगाम लगाने को जारी ये दिशा-निर्देश छात्रों के शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं कि उन्हें झूठे वायदों से गुमराह नहीं किया जाए या अनुचित अनुबंधों में मजबूर न किया जाए।

समलैंगिक विवाह भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात

सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के प्रकरण पर विचार चल रहा है। इस विषय पर समलैंगिक विवाह के पक्षधर लोगों द्वारा यह दलील दी जा रही है कि समलैंगिक लोगों को विवाह का अधिकार नहीं देना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत केवल महिला और पुरुष को एक दूसरे से विवाह के करने की स्वीकार्यता का प्रावधान है। मामले को न्यायालय में ले जाने वालों की दलील है कि इस प्रावधान का जैंडर न्यूट्रल होना चाहिए। केंद्र सरकार का स्पष्ट कहना है कि ऐसा कोई अधिकार उसे विवाह की परिभाषा बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इस प्रकार की शादी को मान्यता दी गई तो समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इससे कई अन्य कानूनों के प्रावधान भी प्रभावित होंगे। सरकार के साथ ही समाज में भी बड़ा वर्ग है जो इस तरह के विवाह को मान्यता दिए जाने का विरोध कर रहा है। लगभग सभी का तर्क यही है कि इससे समाज में परिवार नाम की संस्था के अस्तित्व पर संकट आएगा। समाज का ढांचा प्रभावित होगा। उनका कहना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर भी समलैंगिक विवाह को स्वीकार्यता मिलना संभव नहीं है। अदालत में सुनवाई के साथ कई समूहों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की स्थिति में आने वाले वैधानिक संकट और समाज पर इससे पड़ने वाले प्रभावों की पड़ताल हम सभी के लिए बड़ा मुद्दा है।

भारत में प्राचीन परंपरा व्यक्ति के जीवन से मृत्यु तक सोलह संस्कारों की रही है। सोलह संस्कारों में शुभ विवाह को पाणिग्रहण संस्कार कहा जाता है। लगभग सभी समाजों में युवक एवं युवती की जन्म कुंडली गृह नक्षत्रों के मिलान कर ही शुभ विवाह करने का प्रावधान है। जैन दर्शन के मर्मज्ञ एवं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अभिभाषण विनय कुमार जैन निवासी गुना ने समलैंगिक विवाह की मांग पर अपने मुखर विचार व्यक्त किए हैं उनका कहना है जैन दर्शन में धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से संसार के भव भ्रमण का नाश करते हुए मोक्ष पद की प्राप्ति करना ही व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। और इसके लिए सर्वोत्तम साधन अविवाहित रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। लेकिन यदि किन्हीं परिस्थितियों के कारण व्यक्ति को अविवाहित रहना संभव न हो और उसे विवाह करना आवश्यक ही हो तो वह अपने वैवाहिक जीवन में एकनिष्ठ रहते हुए मुक्तिपथ का अनुगामी हो सकता है । जैन दर्शन में और भारतीय संस्कृति में वैवाहिक जीवन को गृहस्थाश्रम कहा गया है। इस अवस्था को गृहस्थ धर्म का पालन करना भी कहा गया है। विवाह का अर्थ कामवासना में लिप्त हो जाना नहीं है, अपितु संयम की साधना करते हुए वंशवृद्धि के लिए उत्तम संतान को जन्म देना भी है, इस संतान को श्रेष्ठ संस्कार देना भी गृहस्थ धर्म का एक दायित्व है। जिससे वह संतान आगे चलकर धर्म वृद्धि करते हुए स्वयं का और अन्य जीवों का कल्याण कर सके। इस प्रकार स्थूल रूप में कहें तो वैवाहिक जीवन सदाचार को बढ़ावा देने के लिए वंश, समाज और धर्म की वृद्धि के लिए है तथा इसमें व्यभिचार का कोई स्थान नहीं है। इसके माध्यम से आदर्श सामाजिक जीवन जिया जाता है।

इन दिनों समलैंगिक विवाह को सामाजिक और विधिक मान्यता देने के लिए बहुत आग्रह किए जा रहे हैं। किंतु ये आग्रह प्रथम दृष्टया ही दुराग्रह प्रतीत होते हैं क्योंकि वैवाहिक जीवन जिसे गृहस्थ धर्म का पालन करने की संज्ञा दी गई है केवल और केवल विपरीत लिंगधारी अर्थात स्त्री- पुरुष के मध्य ही संभव हो सकता है। दो समलिंगी परस्पर एक दूसरे के अच्छे मित्र हो सकते हैं, वे एक दूसरे के जीवन यापन में भौतिक उन्नति प्रदान करने के लिए सहायक हो सकते हैं। और ब्रह्मचर्यपूर्वक रहते हुए एक दूसरे को धर्म पथ पर अग्रसर रहने में सहायक हो सकते हैं। वे साथ-साथ रहकर भी अच्छे नागरिक बने रह सकते हैं। परंतु ऐसे साथ-साथ रहने को विवाह नाम के पवित्र गठबंधन का नाम नहीं दिया जा सकता है। समलैंगिक विवाह को सामाजिक और विधिक मान्यता दिलाने की मांग जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों की स्थापना करने के लिए नहीं है अपितु व्यभिचार को सामाजिक मान्यता दिलाने का दुराग्रह मात्र ही है।

गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने वंश, धर्म और संस्कारों की रक्षा के लिए संतान उत्पत्ति का लक्ष्य भी समलैंगिक विवाह के द्वारा समाप्त ही हो जाएगा। अंग्रेजी शासन काल में लॉर्ड मैकाले ने गहन अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि भारतीय संस्कृति में गुरुकुल पद्धति के माध्यम से शिक्षा और संस्कृति के जिन आदर्श संस्कारों का बीजारोपण करते हुए आदर्श नागरिकों का निर्माण किया जाता है, उन गुरुकुल को नष्ट किए बिना अंग्रेजी शासन को भारतवर्ष में बनाए रखना संभव नहीं है क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली जीवन में आत्मोन्नति के संस्कार देती है और यह संस्कार गुलामी के बंधन में बांधे रखने में बहुत बाधक हैं। अत- अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति को आमूलचूल रूप से नष्ट किया और उसके दुष्परिणाम सामने आए। इसी प्रकार समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग हमारे दर्शन और उच्च नैतिक जीवन के संस्कारों के हरे-भरे और घने वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करने के समान है। ऐसी मांग की कुल्हाड़ी की धार को समय रहते ही नष्ट नहीं किया गया तो हमारे गृहस्थ धर्म को और उच्च नैतिक मापदंडों पर आधारित सामाजिक जीवन को शनै- शनै- नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसएन ढींगरा का मत है समलैंगिक संबंध भारत में अपराध नहीं है हालांकि समाज इन्हें विवाहित जोड़े के रूप में न स्वीकारता है और न ही ऐसे जोड़े को विवाहित जोड़ा कहने के योग्य मानता है। विवाह पति-पत्नी के बीच की जिम्मेदारी है। यह मानव जीवन का संस्कार है जो समाज को मजबूत करता है। श्री जयप्रकाश नारायण मिश्रा पीजी कॉलेज लखनऊ में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद चंद्रा कहते हैं कि समलैंगिक विवाह को मान्यता जटिल मसला है। एक ओर इस समुदाय के साथ समानता का तर्क है तो दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था। निस्संदेह इस दिशा में बहुत संभल कर ही किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। वेनेशियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि समलैंगिक संबंध रखने वालों में एचआईवी एड्स का खतरा ज्यादा देखा गया है, इनमें नशे की लत, अवसाद, हेपेटाइटिस और यौन संचारित रोगों एसीडिटी के होने की आशंका भी ज्यादा देखी गई है।

कुछ इस प्रकार के कैंसर का खतरा भी ऐसे लोगों में ज्यादा रहता है। हालांकि एक वर्ग है जो ऐसी बहुत सी बीमारियों के लिए उन्हें समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलने के कारण मानता है। 2008 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने समलैंगिकता और यौन इच्छा को लेकर कहा था इस बात को लेकर एक राय नहीं है कि यौन रुझान का कारण क्या है हालांकि कई शोध में पाया गया है कि आनुवंशिक एवं हार्मोन संबंधी कारण परवरिश सामाजिक एवं सांस्कृतिक माहौल से व्यक्ति की यौन इच्छा पर प्रभाव पड़ता है इसका कोई एक कारण नहीं है प्रकृति और परवरिश दोनों की ही इसमें भूमिका रहती है।

नौं निहालो की जान के साथ ये कैसा खिलवाड़

मामला उचेहरा जनपद के गढौत के रार स्कूल का

उमेश कुशवाहा | सिटी चीफ

उचेहरा, दरअसल पूरा मामला परसमनिया पठार की ग्राम पंचायत गढौत का है जहां 6 बच्चों के लिए सरकार लाखों रुपये खर्च कर आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया है सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत जिसकी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत गढौत है यह स्कूल निर्माण के समय से ही सुर्खियों ने रहा था । जनपद में सरकारी पदों ने बैठे जिम्मेदारों ने जिस तरह से सरकार की मन्सा पर पानी फेरते सरकारी पैसो का बन्दर बांट करने का तरीका निकाला जब तक उसकी उच्च स्तरीय जांच नही होगी तब तक सारी हकीकत सामने नही आ पाएगी ।

दरअसल इस पंचायत के जो सचिव सरस्वती चरण सोनी है वो अपनी मीठी वाणी से सबकों जल्द अपने गिरफ्त में ले लेते है जिसने भी घटिया निर्माण का विरोध किया उसको अपने ढंग से गुमराह करते रहे। विद्यालय के मेन गेट के पास जो एक कमरा गाडर और पटिया की छत का बना है, ग्रामीणों से मिली पुख्ता जानकारी अनुसार पंचायत के सचिव सरस्वती चरण सोनी ने यह कमरा सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पहले ही बनवा लिया था इसकी जब तक लोगो को सच्चाई का पता लगा कि यहां तो स्कूल बनना है आनन --फानन अपनी कमी को छिपाने पंचायत ने उसी गाडर और पटिया वाले मकान के बगल में जहां वर्तमान समय मे स्कूल लग रहा है उसका निर्माण पंचायत ने शुरु करा दिया पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमलसिंह मरकाम की माने तो उस समय निजी भवन जानकर उन्होंने कोई आपत्ति नही उठाई लेकिन उसी के बगल में जब सर्व शिक्षा अभियान के मद से बन रहा नया भवन जिसकी जांच हो उस नये भवन में नीचे से पिलर ही नही

पत्थर की नींव भरी गई है इस भवन के निर्माण के समय अधिक मात्रा में डस्ट डाल कर बनाया गया है काम कर रही महिला मजदूरों और कारीगर की माने तो 10 तगाड़ी डस्ट और 3 तगाड़ी रेता मिलाकर यह स्कूल बनाई गई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने जब उस समय हो रहे घटिया निर्माण की आपत्ति उठायी थी तो उस समय उनको भी गुमराह पंचायत के जिम्मेदारो ने किया था गाडर और पटिया की छत का मकान जो उस समय बन रहा था जिला पंचायत सदस्य के अनुसार उस समय उसी वार्ड की जनपद सदस्य आगे आते कहा था कि यह हमारा मकान बन रहा है। कोई भी शासकीय निर्माण होता है के निर्माण के पहले किस एजेंसी निर्माण कर रही है और उसकी लागत भी बोर्ड में लिखी होती है ,जिला पंचायत के जिम्मेदार अगर एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराये तो सारी सच्चाई सामने आते देर नही लगेगी,गढौत पंचायत के कई ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अगर ग्राम पंचायत के अब तक हुये कामो की जांच जिला कलेक्टर महोदय कराये तो कई बड़े घोटाले पंचायत के सामने आ सकते है ।

उठ रहे कुछ सवाल

जिम्मेदार दो इनका जबाब

1- कवरेज के दरमियान मिले शिक्षक राजेश सोनी ने जरुर आफ कैमरे में बताया कि मेन गेट के पास की बिल्डिंग में जो बनी है अभी भी जो उस बिल्डिंग में ताला लगा है उसकी चाभी पंचायत के पास है

2- जिस समय रार स्कूल बन रही थी जनपद सी ई ओ प्रभा टेकाम ने कितनी बार उस स्कूल का निरीक्षण किया अगर उनका विजिट रजिस्टर वरिष्ट अधिकरी चेक करे तो सारी हकीकत सामने अपने आप आ सकती है ।

3-कुछ इसी प्रकार जनपद के सहायक यंत्री सलिल सिंह के विजिट रजिस्टर की भी जिले के अगर वरिष्ट अधिकारी चेक करते है तो सब की मिली भगत सामने आते देर नही लगेगी क्योंकि इस स्कूल की निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत ही है द्य

3- जिनकी देख रेख में आखिर शासन की इतनी बड़ी राशि खर्च हुई उस समय के तत्कालीन इंजीनियर सर्व शिक्षा अभियान के अजय तिवारी ही थे अगर स्वतन्त्र एजेंसी जांच करती है तभी सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जायेगी । आखिर किसकी सर परस्ती में शासन के लाखो रुपयों का बन्दर बांट हुआ।

4- विद्यालय में पढ़ रहे नौ निहालो का क्या कसूर पता नही कब कोई अनहोनी हो जाय इसका जिम्मेदार होगा कौन ?

5- आखिर जब विद्यालत के मेन गेट के पास बने भवन में विद्यालत का नाम लिखा है उसको देखकर ही माना जा सकता है कि यह गाडर ,पटिया का बना भवन भी शिक्षा विभाग के हैंड ओवर हो चुका है भले ही यहां पदस्त शिक्षक श्री सोनी जी आफ कैमरा कह रहे हो कि इस भवन की चाभी पंचायत के पास है। रार का प्राथमिक स्कूल संकुल केंद्र पहाड़ी के अन्तर्गत आता है।

इनका कहना

1- जिस समय यह विद्यालय बन रहा था उस समय भी मैने गुणवत्ता विहीन बन रही स्कूल का विरोध किया था ,घटिया निर्माण में जो भी शामिल हो उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये और दोषियों से शासन की राशि की पूरी रिकवरी होनी चाहिए जिससे भ्रटाचार को बढ़ावा न मिले - **पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमल सिंह मरकाम ।**

2- रार के प्राथमिक विद्यालय के घटिया निर्माण का मामला मेरे संज्ञान में आया है जिला सी ईओ से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग मैं करूंगी - **विमला कोल सदस्य ,जिला पंचायत वार्ड 7 ।**

3 - हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है इस पूरे मामले की मैं निष्पक्ष स्वतन्त्र एजेंसी से जांच कराने की मांग जिले के जिम्मेदारों से करूंगा - **सतीश मिश्रा, जिला- अध्यक्ष, भाजपा।**

आदिवासियों की फसल जेसीबी से नष्ट किए जाने पर डॉ. रश्मि सिंह ने जताया विरोध, तत्काल रुकवाया कार्य..

उमेश कुशवाहा | सिटी चीफ

सतना, जिले के ऊंचेहरा तिघरापाठा में आदिवासियों की फ़सल वन विभाग द्वारा प्लांटेशन के नाम पर जेसीबी से नष्ट किए जाने पर डॉक्टर रश्मि सिंह ने मौक़े पर पहुंचकर विरोध करते हुए तत्काल कार्य को रुकवा दिया है, मामले में डॉक्टर रश्मि सिंह ने कहा कि परसमानिया पठार और इसके आस-पास के आदिवासी समुदाय आज बिजली, पानी, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने संघर्ष कर रहे हैं, तीन पीढ़ियों से अपनी जमीन पर खेती करने वाले इन आदिवासियों की जमीनों पर अब विकास के नाम पर बाड़े लगाए जा रहे हैं, जिससे इनकी जीविका और अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, और आज बन विभाग द्वारा उनकी फसल नष्ट किए जाने की कार्यवाही करना अत्यंत निंदनीय है, डॉक्टर रश्मि सिंह एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा वहां 5 घंटे धरना प्रदर्शन किया गया, डॉक्टर रश्मि सिंह के वरिष्ठ अधिकारीयों से बात करने के पश्चात निर्णय लिया कि आदिवासियों की फ़सल में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तत्पश्चात अधिकारीयों द्वारा आश्वसान मिलने पर धरना समाप्त हुआ, प्रमुख रुप से कांग्रेसी कार्यकर्ता रामबिहारी परौहा, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री चंद्रभान सिंह, बलीराम सिंह, रामसुरेंद्र सिंह,यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रामजस प्रजापति, राकेश यादवर,महेन्द्र सिंह , रकुल कोल, महेन्द्र कोल एवं सरपंच दादूराम कोल एवं सैकड़ों आदिवासी परिवार उपस्थित रहें।

पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में त्वरित समाधान

कानून व्यवस्था पर सख्ती

उमेश कुशवाहा | सिटी चीफ

मैहर, जिले के पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल कानून व्यवस्था को लेकर सख्त माने जाते हैं। प्रत्येक मंगलवार को अपने कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए जिले की जनता की समस्याओं को सुनते हैं और तत्काल समाधान के निर्देश जारी करते हैं।मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान एसपी सुधीर अग्रवाल ने प्रत्येक फरियादी की बात को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए।जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक स्वयं फरियादियों से आमने-सामने बातचीत करते हैं, जिससे लोगों को अपनी समस्याएं स्पष्ट रूप से रखने का अवसर मिलता है। इसी के तहत कई मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया।जनसुनवाई में भाग लेने वाले नागरिकों ने एसपी की कार्यशैली की सराहना की और कहा कि उनकी समस्याओं का निवारण तेजी से हो रहा है। पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। पुलिस अधीक्षक की यह पहल न केवल लोगों की समस्याओं को हल करने में सहायक है, बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास को भी मजबूत कर रही है।

बिजली गुल होने से परेशान दस गांव के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की शिकायत

भगवान दास बैरागी | सिटी चीफ

शाजापुर, जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण दस गांवों के ग्रामीण बिजली गुल होने की समस्या से परेशान हैं। समय पर बिजली नही मिल पाने की वजह से जहां ग्रामीणों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं तो वहीं गांव के किसानों को कृषि कार्य करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बीते कई दिनों से बिजली संकट का सामना कर रहे ग्रामीणों ने परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। ग्राम लड़ावद, भाटखेड़ी, लाहोरी, मेंहदी, रिछौदा सहित दस गांवों के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां मौखिक रूप से शिकायत कर बताया कि अधिकारियों की सुस्त और उदासीन कार्यशैली के कारण गांव में 10 घंटे में से महज 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है जिसकी वजह से अन्य कामों के साथ खेती-किसानी का कार्य प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में रबी फसल की बोवनी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं किंतु बिजली नही होने से बोवनी का काम करना मुश्किल साबित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होने बिजली कंपनी लाहोरी ग्रीड के अधिकारी को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन वह समस्या का समाधान नही कर रहे हैं। ग्रामीणों ने गांवों में दस घंटे सुचारू रूप से बिजली सप्लाय किए जाने की मांग की है।

जनसुनवाई में 87 आवेदन प्राप्त

मुख्यमंत्री जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत मंगलवार को संपन्न हुई जनसुनवाई में 87 आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई कलेक्टर ऋजु बाफना ने की। इस दौरान अपर कलेक्टर बीएस सोलंकी, जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर, अनुविभागीय अधिकारी मनीषा वास्कले ने भी जनसुनवाई में आए आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया। जन सुनवाई में ग्राम सतगांव की महिला ने आवास योजना का लाभ नही मिलने की शिकायत की। महिला ने बताया कि वह अत्यंत गरीब है और योजना के लिए पात्र है उसे योजना का लाभ दिया जाए। वहीं बक्सुखेड़ी की महिला ने समग्र आईडी में नाम जुड़वाने और लाड़ली बहना योजना का लाभ दिलाने की मांग की। इसी तरह रास्ता बंद करने, राशन कार्ड बनवाने सहित अन्य शिकायतों से संबंधित आवेदन जन सुनवाई में दिए गए।

विश्व शौचालय दिवस पर सफाई मित्रों को किया सम्मानित, स्वच्छता की दिलाई शपथ

भगवान दास बैरागी | सिटी चीफ

शाजापुर, विश्व शौचालय दिवस पर मंगलवार को शाजापुर बस स्टैंड स्थित जन सुलभ सुविधा केंद्र पर रंगोली बनाई गई। राजकुमार अकेला ने बताया कि सफाई मित्र निरंतर शौचालय की साफ -सफाई करते हैं और उन्हीं के प्रयासों से हमें शौच एवं स्नान आदि कार्यों के लिए साफ एवं स्वच्छ शौचालय मिलता है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा सफाई मित्र श्याम एवं केयरटेकर सतीश झा को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं उपयोगकर्ताओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए सामूहिक रूप से स्वच्छता की शपथ दिलाई गई।

विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा

सुरक्षित एवं स्वच्छ शौचालयों तक पहुंच और उपयोग तथा स्वच्छता पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस से हमारा शौचालय हमारा सम्मान शुरू हुआ जिसका समापन 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस पर होगा। जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर ने बताया कि जिले की सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया गया है कि विभागीय समन्वय स्थापित कर अपनी जनपद पंचायत अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन करें। सीईओ ने बताया कि आईएचएचएल के लिए पंजीकरण अभियान चलाने तथा सभी पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश वितरित कर शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने के लिए ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत शौचालय प्रतियोगिता तथा ब्लॉक, जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक स्वच्छता परिसर प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए भी कहा गया है। प्रतियोगिता के विजेताओं को जनपद एवं जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। सभी जनपद पंचायतों में इस अभियान को प्रभावी बनाने में आवश्यक अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया गया है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ अंतर विभागीय बैठकें आयोजित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों, विद्यालय परिसरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों आदि संस्थानों में क्रियाशील शौचालय बनाएं तथा उनका रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। समस्त सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में नलजल से जल आपूर्ति की उपलब्धता एवं उपयोगिता सुनिश्चित करें। पीएचसीएस, सीएचसीएस, स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, एएनएम केन्द्रों आदि में शौचालय की कमी का आंकलन कर सीएसआर, विभागीय और एसबीएम निधियों का लाभ उठाकर शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, सफाई कर्मचारियों के असाधारण योगदान का जश्न मनाने एवं उन्हें आवश्यक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सम्मान शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में प्राप्त हुए 32 आवेदन

सहायक कलेक्टर एसडीएम अनूपपुर एवं संयुक्त कलेक्टर ने आवेदकों की सुनी समस्याएं

सुशिल सोनी | सिटी चीफ

अनूपपुर, कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में मंगलवार को जनसुनवाई में जिले के विभिन्न स्थानों से पहुंचे लोगों ने सहायक कलेक्टर एसडीएम अनूपपुर श्री महिपाल सिंह गुर्जर एवं संयुक्त कलेक्टर श्री दिलीप कुमार पाण्डेय को अपनी समस्याएं बताई और आवेदन दिये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों के समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिये। उन्होंने विभिन्न आवेदनों का मौके पर निराकरण भी कराया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी लोगों की समस्यायें सुनी। कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई में 32 आवेदन प्राप्त हुए।

जनसुनवाई में ग्राम वेंकटनगर तहसील जैतहरी निवासी प्रेमलाल नापित ने भूमि का रिकार्ड सुधार कराए जाने, ग्राम डोंगराटोला तहसील अनूपपुर निवासी श्री ओमकार सिंह गोंड़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने, वार्ड नं. 01 सामतपुर (अनूपपुर) निवासी रामकृष्ण राठौर ने उनके पट्टे की भूमि पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने, ग्राम खम्हरिया तहसील अनूपपुर निवासी हरी प्रसाद यादव ने आम निस्तार वाले रास्ते को अतिक्रमणमुक्त कराए जाने, ग्राम पिपरिया तहसील अनूपपुर के काशी पटेल ने उनके पट्टे की भूमि पर लगी धान की फसल को चोरी से काट लेने पर कार्यवाही किए जाने, ग्राम कुम्हरवार जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ निवासी बुद्धेलाल बचावले ने जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत पड़रिया में सरपंच एवं सचिव द्वारा निर्माण कार्य में की गई वित्तीय अनियमितता के संबंध में आवेदन दिए।

बकाया का भुगतान ना करने वाली चीनी मिलों को गन्ना ना देने पर अड़े किसान

गौरव सिंघल | सिटी चीफ

सहारनपुर, सहारनपुर की तीन चीनी मिलों पर 87.55 करोड़ रूपए गन्ना मूल्य का बकाया है। इन क्षेत्रों के किसानों में भुगतान ना मिलने को लेकर भारी रोष व्याप्त है। शाकुम्बरी चीनी मिल टोडरपुर पर 12 करोड़
77 लाख रूपए बकाया है। वहां के सैकड़ों किसानों ने एसडीएम नकुड़ संगीता राघव से मिलकर मांग की है कि भुगतान ना होने की हालत में वे इस चीनी मिल को आपूर्ति नहीं करना चाहते। उन्होंने एसडीएम से कहा है कि उनके क्षेत्र के गन्ने की आपूर्ति दूसरी चीनी मिलों को कराने का काम किया जाए। इस संबंध में जिला गन्नाधिकारी सुशील कुमार ने कहा है कि तीनों चीनी मिलों के प्रबंधकों ने भरोसा दिया है कि नवंबर माह के अंत तक बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। बजाज समूह की गांगनौली चीनी मिल पर 58 करोड़ 19 लाख रूपया और गागलहेड़ी चीनी मिल पर 16 करोड़ 59 करोड़ रूपया बकाया है। यह अलग बात है कि जिले की सभी चीनी मिलों ने गन्ना पेराई शुरू कर दी है और देवबंद चीनी मिल ने तो अभी तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान भी कर दिया है। दूसरी चीनी मिल क्षेत्रों के किसानों बृजेश सैनी, परवेश, नरेश यादव और चौधरी ताहिर का कहना है कि जब देवबंद चीनी मिल चालू पेराई सत्र का भी भुगतान कर रहा है तो बाकी चीनी मिलें पिछले बकाया का भुगतान भी नहीं कर पा रही है जिससे उन्हें गेहूं की बुआई के लिए बीज और खाद के लिए पैसा उधार लेना पड़ रहा है और अब तो शादी एवं अन्य समारोह में खर्च करना भी भारी पड़ रहा है।

रोस्टर, नियुक्ति में भ्रष्टाचार को लेकर जनजातीय विश्वविद्यालय शिक्षकों के दो गुटों में जबरदस्त भिड़ंत

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ

अमरकंटक । अनूपपुर, कुलपति प्रो श्रीप्रकाशमणि त्रिपाठी का कार्यकाल 5 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जायेगा, आखिरी समय में कुलपति ने जबरदस्त भ्रष्टाचार करके टीचिंग तथा नॉन-टीचिंग के पदों पर फर्जी भर्ती प्रक्रिया में तेजी ला दिया है और इसी भ्रष्टाचार रोकने का एक गुट और भ्रष्टाचार करवाने वाले दुसरे गुट में जबरदस्त भिड़ंत से विश्वविद्यालय में अराजकता व्याप्त हो गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के सामने दिनाँक 18 नवम्बर 2024 को सुबह 11:30 बजे विश्वविद्यालय में व्याप्त कई विसंगतियों तथा भ्रष्टाचार के मामले में शिक्षक संघ ने पारदर्शी प्रथाओं को बनाए रखने, भारत सरकार के मानदंडों का पालन करने और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सुधार, नियुक्ति/पदोन्नति में विसंगतियों ठीक करने के मुद्दा के लिए एकत्रित हुए थे। तभी कुलपति समर्थक शिक्षकों का एक समूह (जो शिक्षक संघ के वास्तविक सदस्य भी नहीं हैं) ने सामूहिक रूप से और जानबूझकर शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार, हाथापाई, और मारपीट करके परिसर की शांति को बाधित करने का प्रयास किया है।

राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी को शिक्षक संघ ने सार्वजनिक तथा अलग से गोपनीय पत्र भेजी टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रो भूमि नाथ त्रिपाठी, उपाध्यक्ष प्रो. तरूण ठाकुर, डॉ. नारायण पी. भोसले, महासचिव डॉ. वीरेंद्र प्रताप, संयुक्त सचिव डॉ. चार्ल्स वर्गीस, डॉ. रोहित रवीन्द्र बोर्लिकर तथा कोषाध्यक्ष डॉ. आनंद सुगंधे ने संघ की ओर से घटना की शिकायत राष्ट्रपति भवन, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में किया गया है। रिक्रूटमेंट सेल में भारी भ्रष्टाचार को लेकर शिक्षक संघ ने 23 अगस्त 2023, 10 अगस्त 2024, 19 सितंबर 2024, 15 नवंबर 2024 सहित अनेक पत्र सेंट्रल विजिलेंस कमिशन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा है, कई मामले सेंट्रल विजलेंस कमीशन में पंजीबद्ध होकर जांच किए जा रहे हैं तथा कुछ मामले सीबीआई के पास भी पेंडिंग है जिसमें बड़ी गिरफ्तारी होने की संभावना जताई जा रही है।

शिक्षक संघ के खिलाफ रचा गया बहुत बड़ा षड्यंत्र नाकाम हुआ सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की पूर्व रात्रि साजिश रची गई जिसमें शामिल पूर्वांचल से आए हुए समाजवादी गुंडा शिक्षकों द्वारा शिक्षक संघ के पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार, जबरदस्त पिटाई करने तथा तत्काल इसकी एफआईआर दर्ज कराकर सस्पेंड करने की योजना थी, लेकिन शिक्षक संघ के पदाधिकारी ने अपनी सहनशीलता, धैर्य दिखाते हुए किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने चुपचाप अपने साथ होते हुए घटनाक्रम को सहन कर लिया, जिसके कारण शिक्षक संघ के पदाधिकारी पीटने, जेल जाने और सस्पेंड होने के बड़े षड्यंत्र से बच गए।

एसडीओपी तथा एसडीएम पुष्पराजगढ़ को भी बदनाम कर रहा है विश्वविद्यालय प्राप्त सूत्रों के जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रार प्रो. एन.एस. हरि नारायण मूर्ति तथा उपकुलसचिव डॉ संजीव सिंह 18 नवम्बर 2024 को एसडीओपी तथा एसडीएम पुष्पराजगढ़ के साथ काफी समय तक बैठे थे तथा कुछ प्रोफ़ेसर अमरकंटक थाने के बाहर खड़े थे, अंत में काफी बड़े स्तर पर मामला को सेटल बताया गया है। एक सहायक कुलसचिव ने एसडीएम को रीवा कनेक्शन बताते हुए बात करके उनका फोन टेप कर लिया है, कुछ अधिकारियों को सेट करने लिफाफा देकर छात्रों के आंदोलन तथा शिक्षक संघ के जायज मांग को दबाने के लिए धनबल का जबरदस्त इस्तेमाल चर्चा का विषय बना हैं।

कार्यपरिषद् के तीन सदस्यों ने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दी खतरनाक धमकी घटनास्थल पर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के तीन सदस्यों ने जमकर तबाही मचाया। कार्यपरिषद के सदस्य धमकाया की कुलपति जाते-जाते कई लोगों को तबाह कर देंगे कोई भी झूठा आरोप लगाकर निलंबित कर देंगे। हम लोग कार्यपरिषद के सदस्य हैं जो चाहे वह कर सकते हैं, निलंबित कराकर जान से मरवा देंगे, आत्महत्या करने मजबूर कर देंगे। गलत जांच में फंसा कर पूरे परिवार को तबाह कर देंगे। एक सदस्य ने यह भी कहा की हम तो पॉवर का फायदा उठा रहे है, नाममात्र की औपचारिकता करके उच्चतम ग्रेड पे पर प्रमोशन करा लिया है, प्रमोशन की लिफाफा जिस कार्य परिषद में खुली उसमें वे सभी लाभार्थी उपस्थित रहे हैं। शिक्षक संघ के खिलाफ 90 शिक्षकों द्वारा एक ही पत्र पर हस्ताक्षर करके दिया गया है, इसमें कार्यपरिषद् के सदस्य भी शामिल थे जिन्होंने हस्ताक्षर भी किया है, इसका मतलब कार्यपरिषद् सदस्य अपने शक्ति का षड्यंत्रपूरक बेहद गलत इस्तेमाल कर रहे है, जो संवैधानिक रूप से पूर्णतः वर्जित है कार्यपरिषद के सदस्यों की जाँच के लिए उच्च स्तरीय पत्र लिखा जा चुका है, जिसमें कार्यपरिषद के सदस्यों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।

विश्वविद्यालय से लगभग दो दर्जन गिरफ्तारियां संभावित एससी-एसटी-ओबीसी के उम्मीदवारों को नुकसान करने के लिए रोस्टर रजिस्टर में छेड़छाड़, फर्जीवाडा एवं कुटरचित दस्तावेज का इस्तेमाल करके नियुक्ति करने का कार्य किया है, कार्यपरिषद के किसी भी मिनिट्स में किसी भी सदस्यों का हस्ताक्षर न कराकर जबरदस्त अपराध को अंजाम दिया है जिसमें कम से कम दो दर्जन गिरफ्तारियां संभावित बताई जा रही है।

स्वच्छकारों को सरकारी योजनाओं का प्राथमिकता से मिले लाभ - भगवत प्रसाद मकवाना

सदस्य सेन्ट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिकारियों के साथ की बैठक

गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।

सहारनपुर, सदस्य सेन्ट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय, भारत सरकार भगवत प्रसाद मकवाना ने सर्किट हाउस सभागार में मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के लागू होने व पालन करने के सम्बन्ध में अधिकारियों के समीक्षा बैठक की। भगवत प्रसाद मकवाना ने निर्देश दिए कि जनपद में 10 दिन के अंदर मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के अनुसार पात्र सभी का का सर्वेक्षण करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिनियम में उल्लिखित सफाई से संबंधित विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को सर्वेक्षण में शामिल किया जाए। मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के तहत जनपद के 2811 चयनित लाभार्थियों को भी इस सर्वेक्षण में शामिल किया जाए। जल संस्थान में कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को भी सर्वे में शामिल किया जाए। उन्होंने जनपद में होने वाले सर्वे में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, समिति के सदस्यों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को एक दूसरे का सहयोग कर अधिक से अधिक पात्रों को शामिल कर योजना से लाभान्वित कराया जाए।उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ स्वच्छकारों को दिलाने में संवेदनशीलता बरतें। स्वच्छकारों की बस्तियों में समय-समय पर स्वास्थ्य एवं लोन शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छकारों की बस्तियों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जनपद में आउटसोर्सिंग, ठेका एवं अन्य माध्यमों से नगर निकायों में तैनात सफाई कार्मिकों के वेतन भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई एवं साप्ताहिक अवकाश की जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि किसी भी कार्मिक का शोषण न हो। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर स्वच्छकारों के नियमानुसार भुगतान एवं प्रदत्त सुविधाओं में गड़बड़ी पाई जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छकार एवं अन्य पदों पर कार्यरत आउटसोर्स एवं संविदा कार्मिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय दिलाना सुनिश्चित किया जाए।सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश व प्रदेश सरकार द्वारा सफाई कार्य में लगे हुए स्वच्छकारों के लिए लाभकारी योजनाएं संचालित कर पुनर्वासित किया जा रहा है। स्वच्छकारों के पुर्नवासन के लिए स्वच्छकारों की बस्तियों में अधिक से अधिक कैम्प लगाकर ऋण वितरित किया जाए। भगवत ने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सीवर में कार्य करते हुए मृतक स्वच्छकारों के आश्रितों को 30 लाख मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

बैठक के अन्त में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी ने सदस्य को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके दिये गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। इस अवसर पर एस पी यातायात सिद्धार्थ वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट गजेन्द्र कुमार, जनपद स्तरीय समिति के सदस्य भारत भूषण, विनोद घावरी, डेविड ढींगिया एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

हनुमान चालीसा स्वर पाठ के साथ राजेन्द्र ग्राम में विप्र समाज की बैठक

विप्र समाज अनूपपुर का नेक नियत ईमानदारी निष्पक्षता एवं समाज सेवा भाव समाज के लिए अनुकरणीय - संतोष मिश्रा

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ

अनूपपुर, विगत दिवस को जोहिला नदी के तट पर स्थित अत्यंत ख्याति प्राप्त दक्षिण मुखी संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर परिसर में भगवान परशुराम का मंदिर बनना प्रस्तावित है वहां हनुमान चालीसा के स्वर पाठ विप्र समाज का बैठक मंहत हरिदास महराज के अध्यक्षता में पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रारम्भ हुआ संचालन करते हुए आर्यावर्त ब्राह्मण महासभा अनूपपुर के जिलाध्यक्ष पंडित चैतन्य मिला ने अपनी बात रखते हुए कहा कि विप्र समाज अनूपपुर का मुख्य उद्देश्य समाज के अंदर संस्कार का ज्ञान देने के साथ साथ चंदा से धंधा रहित एवं समाज के कार्यों में राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए रखना है। जिला विप्र समाज के संयोजक मानस मर्मज्ञ पंडित रामनारायण द्विवेदी ने समाज द्वारा चलाए जा रहे पूरे कार्यक्रम का विस्तृत विवरण रखते हुए बताया कि अनूपपुर जिले के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण स्थित समस्त ग्राम नगरीय क्षेत्र में निवासरत विप्र परिवारों को कम से कम 11000 सदस्यों को बनाने के लक्ष्य जिसमें एक नारियल और जनेऊ के साथ बिना चंदा लिए सदस्यता अभियान हेतु समर्थन और सुझाव मांगा,जिस पर उपस्थित सर्व ब्राह्मण समाज पुष्पराजगढ़ के सभी उपस्थित विप्रजनों के द्वारा एक स्वर में सहमति व्यक्त की गई। उपस्थित विप्र वृंद हनुमान जी के भव्य प्रतिमा के आगे अपने अपने सदस्यता के लिए श्रीफल और जनेऊ एवं हनुमान जी एवं परशुराम जी के जयकारे के साथ संयोजक पंडित रामनारायण द्विवेदी को सौंपकर सदस्यता ली। बैठक के कार्यक्रम में सर्व ब्राह्मण समाज पुष्पराजगढ़ के अध्यक्ष अधिवक्ता पंडित संतोष मिश्रा ने राजेन्द्र ग्राम में चलाए जा रहे गतिविधियों की प्रमाणिकता के साथ जानकारी दी तथा विप्र समाज द्वारा चलाए जा रहे गंभीरता पूर्वक समाज को राजनीति से पृथक दिखावा से दूर चंदे के धंधे से दूरी बनाने के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा विप्र समाज अनूपपुर का नेक नियत ईमानदारी निष्पक्षता एवं समाज सेवा भाव समाज के लिए अनुकरणीय है, राजेंद्रग्राम क्षेत्र का समस्त विप्र समाज आपके साथ है।इसी तारतम्य में पुष्पराजगढ़ सर्व ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष पंडित प्रमोद शर्मा जी ने कहा कि हमारा धार्मिक उद्देश्य धार्मिक ज्ञान का प्रसार,आध्यात्मिक विकाश की बढ़ावा,अनुष्ठानों और त्यौहारों का आयोजन तथा धर्म शिक्षा के प्रसार के साथ ही धर्म के मूल्यों को बनाए रखना विप्र समाज का यह उद्देश्य हमारे लिए अनुकरणीय है। सचिव पंडित शीलवंत प्रसाद तिवारी ने कहा कि विप्र समाज के उद्देश्यों में मुख्यतः नैतिक दृष्टिकोण से निष्पक्षता,न्याय,सच्चाई,करुणा,सेवाभाव,सहानुभूति,आत्मविश्वास,जिम्मेदारी की पहचान होती है।

इन्होंने ग्रहण की सदस्यता विप्र समाज के संयोजन पंडित रामनारायण द्विवेदी जी को श्रीफल और जनेऊ सौंपकर बाबा हरिदास ,संतोष मिश्रा,शीलवंत प्रसाद तिवारी,प्रमोद शर्मा,शिवानंद पांडे,नागेंद्र कुमार शुक्ला,शांति भूषण मिश्रा,मोनल तिवारी,सोनल तिवारी,अमन त्रिपाठी,लाल बहादुर दुबे,,रामानंद त्रिपाठी,राजेंद्र चतुर्वेदी जी साथ ही अन्य उपस्थित विप्रवरों ने ली सदस्यता,साथ ही विप्र समाज के संयोजन पंडित रामनारायण द्विवेदी जी के द्वारा सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को राजेंद्रग्राम उसके आसपास के विप्र समाज के परिवार को जोड़ने का उत्तरदायित्व दिया।जिससे 11000 परिवार को जोड़ने में सफलता प्राप्त हो सके। इस पूरे कार्यक्रम में विप्र समाज के जिले के प्रतिनिधि मंडल में पंडित शेष नारायण शुक्ला, पंडित जितेंद्र पांडे,पंडित संदीप मिश्रा भी विप्र समाज के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित जनों से समर्थन मांगे।

हाईटेक नर्सरी के कार्य को संबंधित अधिकारी रूचि लेकर यथाशीघ्र करें पूर्ण :- जिलाधिकारी मनीष बंसल

जिलाधिकारी ने की सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा एवं सीएम डैशबोर्ड पर कुछ योजनाओं में अपेक्षित प्रगति न होने पर संबंधित विभागों की बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि अक्टूबर माह में सीएम डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग 26 है जिसमें से विकास विभाग के खराब रैंकिंग वाले विभागों को उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिन योजनाओं के कारण जनपद की रैकिंग खराब हो रही है उन पर प्राथमिकता से कार्य किया जाए। जनपद की उच्चतर रैंकिंग के लिए विकास एवं राजस्व विभाग के अधिकारी बेहतर कार्य करें। डीएम मनीष बंसल ने अधिशासी अधिकारी सिंचाई को नहरों पर सिल्ट सफाई के कार्य के सत्यापन एवं टेल तक पानी पंहुचाने में लापरवाही करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। शाकम्भरी रेंज में सड़क निर्माण हेतु आ रही समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के संबंधित विभागों को निर्देश दिए। प्रत्येक ब्लॉक में एक अस्थाई गौशाला के निर्माण हेतु खण्ड विकास अधिकारियों को यथाशीघ्र भूमि चिन्हित कर निर्माण हेतु निर्देशित किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मेंटीनेंस में आ रही दिक्कतों के लिए संबंधित अधिकारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। हाईटेक नर्सरी के कार्यों को समय से पूर्ण करने के लिए जिला उद्यान अधिकारी को रूचि लेकर कार्य करने को कहा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आवेदन लेकर इसके समय से टैण्डर की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिए कि कृषकों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान समय से किया जाए। उन्होने कहा कि फैमिली आईडी से संबंधित सभी विभाग लक्ष्य के अनुरूप कार्य में तेजी लाएं। जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित हो रही रैंकिंग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश दिए कि खराब रैंकिंग वाले विभाग अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाएं। सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपनी विभागीय प्रगति की रिपोर्ट सीएम डैशबोर्ड पर माह के अन्त तक अनिवार्य रूप से फीड कराना सुनिश्चित करें एवं अधिकारी स्वयं उसकी मॉनीटरिंग करें। बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सीएम डैशबोर्ड पर आवास, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन, युवा कल्याण, पर्यटन, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन, योजना, राज्य कर, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, भूविज्ञान और खनन, लोक शिकायत द्वारा संचालित कुछ योजनाओं पर बेहतर कार्य न किए जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों की कुछ योजनाओं द्वारा अपेक्षित कार्य नहीं किया गया जिससे जनपद की रैंकिंग प्रभावित हुई है। इस संबंध में उन्होने विभागों के अधिकारियों को प्रगति न होने पर स्पष्टीकरण जारी कर जवाब देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी योजना में कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो उस संदर्भ में अपने मुख्यालय से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, डीएफओ शुभम सिंह, पीडी डीआरडीए प्रणय कृष्ण, डीसी एनआरएलएम इंद्रपाल सिंह, डीएसटीओ अमित कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

71 वॉ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन

अलीराजपुर - आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बखतगढ़ में 71 वीं अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के 6 वे दिन आयोजन जिला सहकारी संघ झाबुआ एवं बी पैक्स बखतगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में समिति प्रांगण में किया गया । आयोजन में प्रभारी उपायुक्त सहकारिता जी.एल. सोलंकी द्वारा महिलाओं ,युवाओं एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सहकारिता द्वारा किए जा रहे कार्यों कि चर्चा की गई । उन्होंने बताया कि सहकारिता द्वारा महिला की 13 समितियों का गठन किया गया केन्द्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सहकारिता से समृद्धि योजना अंतर्गत संचालित 54 पहलुओं के तहत जिले में की जा रही 18 योजनाओं की जानकारी मदवार महिलाओं युवाओं तथा समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सहकारिता के माध्यम से नवीन सहकारी समितियों के गठन पुनर्गठन व डेयरी, मत्स्य पंजीयन के लिए जन समुदाय से आवाहन किया गया तथा इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे 0 प्रतिशत के.सी.सी. ऋण के बारे में बताया गया। कार्यक्रम को जनप्रतिनिधि नरिंग मौर्य ने पशुपालन डेयरी के महत्व पर प्रकाश डाला एवं विशेष अतिथि विक्रम सिंह भयडिया जनपद उपाध्यक्ष सोडवा ने महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही लाडली बहना योजना एवं कमजोर वर्ग के लिए किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी दी एवं संस्था प्रशासक श्रीमती नेहा रायकवार राठौर द्वारा 0 प्रतिशत ब्याज पर के.सी.सी. ऋण योजना के बारे मे कहा । कार्यक्रम में प्रधान मंत्री फसल बीमा के लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला संघ के प्रबंधक दुर्गेश पालीवाल द्वारा किया गया एवं इस अवसर पर समिति प्रबंधक, पर्यवेक्षक, सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। प्रभारी उपायुक्त सहकारिता जी.एल. सोलंकी द्वारा उक्त जानकारी दी गई।

कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ स्नेहलता सिंह राजावत की पुत्री मोहिनी की सगाई, तिलक, रिंगसेरेनमी रस्म में हिंदूवादी नेता नारायण सोमानी हुए शामिल साथ ही मोहिनी, मानवेंद्रसिंह का केसरिया दुपट्टा ओढाकर दी शुभकामनाएं, साथ ही जननेता सोमानी ने दी परिवारजनो को बधाई

जावद। कार्तिक सुदी पुर्णिमा के पावन पर्व पर नीमच निवासी एवं कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष श्रीमती स्नेहलता सिंह राजावत, धीरेन्द्रपाल सिंह राजावत की पुत्री एवं मनोस्मि राजावत, तिर्थसिंह राजावत की बहन मोहिनी राजावत की संगाई, तिलक, रिंगसेरेनमी का भव्य आयोजन महांकाल की नगरी उज्जैन के पास, देवास रोड स्थित नारायणा स्कूल के पास द ग्रांड मोनार्च होटल परिसर पर ढोल-ढमाको, बैंड-बाजो, शहनाईयों की गुंज पर देवास निवासी वीरेंद्र सिंह पंवार, रेणु पंवार के पुत्र मानवेंद्रसिंह पंवार के साथ सम्पन्न हुई। कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ जिला सचिव एवं प्रेस क्लब अध्यक्ष नारायण सोमानी सगाई रस्म के स्टेच पर जाकर मोहिनी संग मानवेंद्र को केसरिया दुपट्टा ओढाकर स्वागत सम्मान करके बधाई दी साथ ही परिवारजनो को शुभकामनाए दी। परिवारजनो की उपस्थिति में मोहिनी एवं मानवेंद्र ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई बंधन में बंधे। इसके पूर्व नीमच जिले में धार्मिक, सामाजिक साथ ही चौथा स्तम्भ पत्रकारिता क्षेत्र में अग्रणी रहने वाले हिंदूवादी नेता एवं प्रेस क्लब अध्यक्ष नारायण सोमानी कार्तिक पूर्णिमा के

पावन पर्व पर प्रातः 4.30 बजे उज्जैन महांकाल मंदिर पहुंचकर क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि की कामना करके महांकाल के दर्शन किए।

खेड़ी क्षेत्र की सफल एवं बहुचर्चित संस्था जीनियस पब्लिक स्कूल में किया गया

खंडवा खेड़ी - क्षेत्र की सफल संस्था जीनियस स्कूल जो की इंग्लिश मीडियम में अनेक आयाम स्थापित कर चुकी है, स्कूल के आधा एकड़ ग्राउंड में सभी बच्चो एवं समस्त स्टाफ के द्वारा विभिन्न प्रकार के पेड़/पौधे लगाये गए। पौधारोपण कार्यक्रम में स्कूल डायरेक्टर श्रीमान कमलेश वर्मा व स्कूल प्राचार्या कल्पना वर्मा भी शामिल रही, पौधारोपण से जीनियस ग्राउंड एक भव्य रूप में दिखा, पौधारोपण कार्यक्रम के बाद स्कूल प्राचार्या ने समस्त बच्चो को अपने जीवन में पेड़ो के महत्व को समझाया।।

शिवसेना ने किया दो लोगों का अंतिम संस्कार

शंभूपुरा। चित्तौड़गढ़ शहर कोतवाली थानान्तर्गत एक युवक की आकस्मिक मृत्यु होने तथा एक अधेड़ मजदूर की अकाल मौत हो जाने व परिवारजनों के अत्यंत निर्धन होने से शिवसेना की ओर से उनका हिन्दू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार एक 35 वर्षीय युवक के कलेक्ट्रेट चौराहे के पास मृत अवस्था में पड़ा मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुँच कर शव को शिनाख्ती के लिए जिला चिकित्सालय मार्चरी में रखवाया जहाँ प्रयास कि बावजूद शिनाख्ती नहीं हो पाई। इसी प्रकार कच्ची बस्ती मोहर मगरी निवासी एक अधेड़ मजदूर की आकस्मिक मृत्यु हो जाने व परिवाजनों के असहाय एवं निर्धन होने से अंतिम संस्कार नहीं कर पाये। अंतिम संस्कार के लिए दोनों ही शवों को शिवसेना जिला प्रमुख गोपाल वेद के सुपुर्द किया गया जिनका शहर स्थित मोक्षधाम में विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कोतवाली थाने के एएसआई अम्बालाल, भारत विकास परिषद के नवीन वर्डिया, रमेश ईनाणी, पुष्कर नराणिया, हेमंत भट्ट, कन्हैयालाल देवपुरा, पार्षद अनिल ईनाणी, मातेश्वरी सेवा संस्था के अध्यक्ष भेरूलाल शर्मा, पप्पू गुर्जर, किशन ओड़, मदन ओड़ आदि उपस्थित थे।

उदयपुर रोड के जाम से परेशान वाहन

कपासन नगर क्षेत्र के मध्य उदयपुर रोड पर प्रतिदिन लग जाता है वाहनों का जाम परेशान होते हैं राहगीर। नगर पालिका प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता।दोपहिया एवं चौपाइयां वाहनो का विद्यालय समय में प्रतिदिन रहता है भारी दबाव। प्राप्त जानकारी के अनुसार उदयपुर रोड पर भारी वाहनों, स्कूल व राजसमंद भीलवाड़ा रूट कि बसों के आवाजाई से जाम की स्थिति बन जाती है। उदयपुर रोड पर दो बसों के पास होने का स्थान कम है और दुकानों के बाहर दुकानदार एवं खरीदारी करने वाले ग्राहकों की गाड़ियों की पार्किंग कम होने की वजह से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर पालिका प्रशासन को इस रोड पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बसो का मार्ग परिवर्तन करने से बार-बार लगने वाले जाम से राहत मिल सकती है । बस स्टैंड से उदयपुर रोड व राजसमंद रोड पर नगर के 6 बड़े विद्यालय है। स्कूल की छुट्टी के समय स्कूल बसों एवं विद्यार्थियों एवं आमजन का दबाव अत्यधिक रहता हैराजसमंद एवं भीलवाड़ा एवं स्कूल बसों को चुंगी नाका से हाईवे की तरफ से ही आना जाना कर दिया जाए तो बार-बार लगने वाले जाम से निजात मिल सकती है। पूर्व में भी पूर्व पालिका अध्यक्ष दिलीप व्यास द्वारा भारी वाहनों को उदयपुर रोड पर आवाजाई की रोक लगाई थी उस दौरान जो परिवर्तित मार्ग था उसे दोबारा से चालू किया जाए एवं पालिका प्रशासन को सख्त कदम उठाते हुए उदयपुर रोड पर भारी वाहनों को आने-जाने से रोक लगाने के क्रम में सुनिश्चित योजना बनाई जानी अति आवश्यक है।

भावसिंगपुरा प्राथमिक शाला में बच्चों को दी कानूनी

खंडवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा के अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती ममता जैन के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अनुपमा मुजाल्दे के समन्वय से सोमवार 18 नवंबर 24को ग्राम भावसिंगपुरा के शासकीय प्राथमिक शाला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। पैरा लीगल वालंटियर नारायण फरकले ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी देते हुए योजनाओं एवं बाल कल्याण समिति, चाईल्ड लाइन बाल श्रम, लैंगिक

अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम,पाक्सो एक्ट गुड टच बेड आदि के संबंध में जानकारी देते हुए योजनाओं से संबंधित पंपलेट वितरण किए गए।इस अवसर पर प्रधान पाठक रिजवाना बेगम,रंगनुम कोशल अनिता भलराय सहित 48 विद्यार्थी उपस्थित थे।

नगर कांग्रेस ने मनाई स्वर्गीय इंदिरा गांधी

कुमावत कपासन नगर कांग्रेस कमेटी कपासन द्वारा भारत की प्रथम महिला प्रधान मंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री मति इंदिरा गाँधी की जन्म जंयती कपासन गांधी वाटिका में उनकी तस्वीर पर पुष्प माला अर्पित कर विचार गोष्ठी कर मनाई गई नगर कांग्रेस प्रवक्ता युवा कांग्रेस जिला महासचिव विजय बारेगामा ने बताया की भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की105वीं जयंती कपासन नगर कांग्रेस अध्यक्ष शंकर लाल प्रजापत की अध्यक्षता में कपासन स्थित गांधी वाटिका मे इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प माला अर्पित कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने विचार रखें इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष शंकरलाल प्रजापत एवं कई वक्ताओं ने इंदिरा गांधी के जीवन एवं कार्यशैली पर विस्तृत जानकारी दी। लौह महिला कि जन्म जयति पर नगर कांग्रेस कमेटी कपासन की और से कांग्रेस पदाधिकारीयों जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं ने हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष सतीश नंदवाना युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीनबंधु सोमानी पार्षद रोशन सोनी पूर्व पार्षद शिव शंकर उपाध्याय ,अनिकेत सोनवाल, अशरफ हुसैन, लक्ष्मी नारायण व्यास नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिरोया, पूर्व पार्षद हरलाल जटिया, युवा जिला महासचिव रोहित कोदली ओबीसी नगर अध्यक्ष सुनील तेली पूर्व ब्लॉक प्रवक्ता मधुसूदन कुमावत युवा नेता रवि सोनी ,अमित मोदी ऋतिक व्यास, सत्यनारायण चोटिया लक्ष्मी लाल भांड, संदीप सोमानी अंकित वैष्णव अशफाक खान असलम मंसूरी, ओम कुमावत भेरुजी ,शांतिलाल माली ,रतन सिंह , रुस्तम शाह, कमलेश राव शानू शेख, जमील खा पठान, मो इलियास मेवाती ,गोपी लाल गुर्जर , लक्ष्मी लाल कुमावत नगर कांग्रेस प्रवक्ता किशनलाल प्रजापत सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहे

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती, क्षेत्रीय नेता पाटीदार का किया

सिंगोली- आज संगोली में ब्लॉक कांग्रेस नगर कांग्रेस द्वारा पार्टी कै नवनियुक्त प्रदेश सचिव सत्यनारायण पाटीदार का अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर भव्य स्वागत किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी के आव्हान व जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया के मार्गदर्शन में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107 वी जन्म जयंती ब्लॉक कांग्रेस, मंडलम, सेक्टर एवं नगर कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को सिंगोली में दोपहर 03:00 बजे नवीन बस स्टेण्ड स्थित कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर कांग्रेस नेता एवं प्रदेश कांग्रेस सचिव सत्यनारायण पाटीदार की उपस्थिति में मनाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107 वी जन्म जयंती कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा श्रीमती गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर मनाई गई।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव सत्यनारायण पाटीदार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनीष जैन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जमील मोहम्मद मेव, एडवोकेट संजय नागोरी, पार्षद राजेश भंडारी व एमडी मंसूरी झातला ने श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं की जानकारी दी।

इससे पूर्व जावद विधानसभा के कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार के प्रदेश कांग्रेस सचिव नियुक्त होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवीन बस स्टैंड पर जमकर आतिशबाजी करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया।

इंदिरा गांधी की जयंती के पश्चात नव नियुक्त प्रदेश कांग्रेस सचिव सत्यनारायण पाटीदार का सभी कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से फूल माला पहनाकर स्वागत किया।

कार्यक्रम का संचालन राजकुमार छीपा ने किया तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का आभार नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश नागोरी ने व्यक्त किया। इस मौके परवरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता बंसी लाल जी शर्मा हजारीलाल धाकड़ सिद्धार्थ बना राजेश बगड़िया पार्षद कमल कुमार शर्मा सत्तू लाल बिश्नोई संजय बगड़िया सुधीर लासोड मंडल अध्यक्ष शिवराज गुर्जर रामलाल गुर्जर लीला शंकर धाकड़ बालकिशन धाकड़ जनपद सदस्य

सेक्टर अध्यक्ष रितेश सेठिया अशोक कुमार धाकड़ अशोक चौधरी दिनेश कुमार पालीवाल एमडी मंसूरी मानक चंद जैन राधेश्याम धाकड़ प्रकाश धाकड़ पूर्व सरपंच अजय मेघवंशी ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश मेघवंशी नारायण मेघवंशी नाथू लाल धाकड़ नरेश जैन महावीर जैन धीरज जैन आजाद नीलकर अतुल मैहर अंकित सेन इकबाल हुसैन बाड़ी खाजा हुसैन अंकित सेन रमेश अंबा

रासेयो इकाई मनासा द्वारा किया गया बाल संरक्षण सप्ताह अंतर्गत बाल चौपाल कार्यक्रम का आयोजन ,बच्चों को किया उनके अधिकारों के प्रति

मनासा/-शासकीय रामचंद्र विश्वनाथ महाविद्यालय मनासा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आज बाल संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत विवेकानंद नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय मनासा (सामुदायिक भवन) में बाल चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यार्थियों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया गया। बाल श्रम नहीं करने एवं रोज विद्यालय आने हेतु प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवक कार्यक्रम अधिकारी प्रो. आशा पटेल एवं प्राथमिक विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

ईरान में जेल में बंद नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ीं

इण्टरनेशनल डेस्क. ईरान में जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी एक जटिल सर्जरी से गुजरीं, जिसके तहत उनके दाएं पैर की एक हड्डी का कुछ हिस्सा कैंसर की आशंका के चलते हटा दिया गया। हालांकि, अधिकार समूहों के मुताबिक, नरगिस को सर्जरी के महज दो दिन बाद वापस जेल भेज दिया गया, जिससे उनकी सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) को भेजे गए 40 से अधिक अधिकार समूहों के हस्ताक्षर वाले एक पत्र में नरगिस को उन आरोपों में सुनाई गई जेल की सजा से तत्काल चिकित्सकीय फर्लो पर रिहा करने का आग्रह किया गया है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से आलोचना हो रही है।

इस पत्र को ईरान पर नरगिस की रिहाई का दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नोबेल समिति के नरगिस को पिछले साल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद से ही ईरान पर उनकी रिहाई का दबाव बनाने का अभियान चलाया जा रहा है सोमवार को भेजे गए पत्र में कहा गया है, हम ईरानी अधिकारियों से मानवाधिकारों का अपराधीकरण रोकने और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों एवं लेखकों की सेहत ठीक न होने पर उन्हें जेल में कैद करने से बचने का आग्रह करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूतावास ने इस पत्र पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं, अतीत में नरगिस की रिहाई के लिए चलाए गए अभियान को तवज्जो न देने वाले ईरान के सरकारी मीडिया ने भी पत्र पर कोई खबर नहीं प्रकाशित की है।

नरगिस (52) राज्य विरोधी तत्वों के साथ मिलीभगत और ईरान सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार के आरोप में कुल 13 साल और नौ महीने की जेल की सजा काट रही हैं। कई बार गिरफ्तार किए जाने और सलाखों के पीछे लंबी अवधि गुजारने के बावजूद उन्होंने अपना अभियान जारी रखा है। पत्र के मुताबिक, जेल में रहने के दौरान नरगिस को कई बार दिल का दौरा पड़ा और 2022 में उनकी आपात सर्जरी की गई थी। नवंबर की शुरुआत में नरगिस के वकील ने बताया कि डॉक्टरों ने उनके दाएं पैर की एक हड्डी में घाव की पुष्टि की है, जिसके बारे में उन्हें आशंका है कि यह कैंसर हो सकता है। इसके बाद बृहस्पतिवार को उनकी सर्जरी की गई।

पत्र में कहा गया है, नरगिस को चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध सर्जरी के महज दो दिन बाद वापस जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। नरगिस को चिकित्सा फर्लो पर रिहा करने और उनकी सजा निलंबित करने के उनके विधि टीम के आग्रह को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इसमें कहा गया है, वर्षों की कैद और महीनों के एकांत कारावास ने नरगिस के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे उन्हें कई ऐसी स्वास्थ्य जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें अस्पताल में बिताई गई छोटी अवधि में संबोधित नहीं किया जा सकता।

एक तीर से साधे 2 निशाने

जाते-जाते बाइडन ने यूक्रेन को दी नई ताकत, रूस और ट्रंप की बढ़ाई टेंशन

इण्टरनेशनल डेस्क. रूस-यूक्रेन युद्ध जमीन पर कब्जे को लेकर जारी है, और इस दौरान यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र के 1000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब, अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मगर सवाल यह है कि बाइडन प्रशासन ने यह फैसला अब क्यों लिया, जबकि पहले इस कदम को टाला गया था? विशेषज्ञों के अनुसार, बाइडन प्रशासन का यह कदम चुनावी रणनीति और रूस पर दबाव बनाने का एक तरीका हो सकता है। यह भी माना जा रहा है कि बाइडन चाहते हैं कि इस युद्ध का अंत उनकी अगुवाई में हो, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को इस पर कोई राजनीतिक क्रेडिट न मिले।

अमेरिका का उद्देश्य है कि कुर्स्क पर यूक्रेनी कब्जा बरकरार रहे, ताकि भविष्य में युद्ध समाप्ति के लिए बातचीत के समय यूक्रेन के पास नेगोशिएशन का कुछ आधार हो।

अगर रूस कुर्स्क क्षेत्र को फिर से कब्जा कर लेता है, तो यह यूक्रेन के लिए एक रणनीतिक नुकसान हो सकता है। इस फैसले से अमेरिका रूस पर एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है और चेतावनी दी है कि यूक्रेन की तरफ से लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल परमाणु हमला करवा सकता है। रूस ने यह भी कहा कि नाटो की मदद के बिना यूक्रेन खुद से यह हमले नहीं कर सकता था।अमेरिका ने अब तक युद्ध में अपने सैनिकों को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया है, लेकिन उसने यूक्रेन को बहुत सारे हथियारों की आपूर्ति की है, जिनमें एफ-16 और आर्टिलरी गन शामिल हैं। अब लॉन्ग रेंज मिसाइलों के इस्तेमाल से यूक्रेन के पास रूस के अंदर तक हमला करने की क्षमता होगी, जिससे युद्ध का दायरा बढ़ सकता है।दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका ने इतने सारे संसाधन यूक्रेन को क्यों दिए, जबकि उसे इससे कोई लाभ नहीं हुआ। इस मुद्दे पर बातचीत का रास्ता खुल सकता है, और आने वाले दिनों में युद्ध के लिए एक निपटारा हो सकता है।

बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में लगी आग, सेल्स गर्ल की मौत

ऑटो डेस्क. कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में मंगलवार शाम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में भीषण आग लग गई। यह घटना राजकुमार रोड पर स्थित माई ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में हुई। शोरूम में आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हालांकि, शोरूम में काम करने वाली एक सेल्स गर्ल प्रिया (20) आग के बीच फंस गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि आग शाम करीब 5:30 बजे लगी। शोरूम में आग लगते ही लोग घबराकर बाहर निकलने लगे। जैसे-तैसे सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन प्रिया अंदर ही फंस गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक शोरूम में खड़ी सभी 45 इलेक्ट्रिक स्कूटर जलकर खाक हो चुके थे।

प्रिया की मौत आग में जलने से हुई, जो शोरूम में फंसी रह गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आग के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। शोरूम मालिक को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

पुलिस की जांच जारी

घटना के बाद से पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है ताकि घटना के कारणों का सही-सही पता लगाया जा सके और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

बिहार में आयोजित होगा महिला संवाद कार्यक्रम

नीतीश कैबिनेट ने 225.78 करोड़ के बजट के आवंटन को दी मंजूरी

पटना. बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को 'महिला संवाद के लिए 225 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन को मंजूरी दे दी।

'महिला संवाद बिहार सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शीर्ष अधिकारी राय की महिलाओं से संपर्क करेंगे।

सूत्रों ने बताया कि संवाद कार्यक्रम 'जिला और प्रखंड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे जिनमें से कई में मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना है, जबकि अन्य स्थानों पर उनके कैबिनेट सहयोगी और शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 'महिला संवाद के लिए 225.78 करोड़ रुपये के बजट के आवंटन को मंजूरी दी गई। राय सरकार के कैबिनेट सचिवालय विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राय सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव दिया गया था। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को महिला सशक्तीकरण से संबंधित सरकार की नीतियों की जानकारी दी जाएगी और सरकार से महिलाओं की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं को जानने का भी प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है कि अगले माह से इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि सरकार जल्द ही इस संबंध में एक परिपत्र जारी करेगी। बिहार के कुल मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 48 फीसदी है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में नीतीश कुमार कैबिनेट ने विभिन्न अभियानों या युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद होने वाले बिहार के सैन्य और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 11 लाख रुपये से बढ़ाकर 21 लाख रुपये करने का फैसला किया। राय के गृह विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष रखे गए उक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि सेना के जवानों के मामले में जो बिहार में शहीद होते हैं, भले ही वे राय के निवासी न हों, उनके परिजनों को 21 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी।

छतरपुरः पुलिस से परेशान महिला ने मांगी आत्महत्या की अनुमति

नॅशनल डेस्क। मध्यप्रदेश के छतरपुर में एक महिला ने पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर एसपी से आत्महत्या की अनुमति मांगी। महिला का आरोप है कि थाने की पुलिस ने सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। इसके बाद महिला ने एसपी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई लेकिन इस पर एसपी ने महिला के आवेदन पर मुहर और हस्ताक्षर कर उसकी रसीद दे दी।

क्या है पूरा मामला?

छतरपुर जिले के हरपालपुर की निवासी शोभा जंगरिया, जो वार्ड नंबर 13 के खटीक मोहल्ले में रहती हैं, ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शोभा के मुताबिक, 10 नवंबर की रात उनके पति राजेंद्र जंगरिया के साथ मोहल्ले के कुछ लोगों ने शराब के नशे में मारपीट की। जब उन्होंने हरपालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी। इससे परेशान होकर शोभा ने सीएम हेल्पलाइन (181) पर थाने की पुलिस के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद थाना प्रभारी पुष्पक शर्मा ने उन्हें शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। शोभा का आरोप है कि जब उन्होंने शिकायत वापस लेने से इनकार किया, तो पुलिस ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी।

आत्महत्या की इजाजत का आवेदन

पुलिस के इस रवैये से तंग आकर शोभा ने 18 नवंबर को छतरपुर के एसपी अगम जैन को आवेदन देकर आत्महत्या की अनुमति मांगी। हैरानी की बात यह रही कि एसपी कार्यालय ने उस आवेदन पर मुहर और साइन करके रसीद के तौर पर शोभा को लौटा दिया। महिला द्वारा साझा किया गया यह आवेदन पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस मामले ने तूल पकड़ लिया और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे। शोभा ने कहा, हमें न्याय नहीं मिला, इसलिए हमने आत्महत्या की इजाजत मांगी। अब हमारे पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है।

एसपी अगम जैन ने आत्महत्या के आवेदन की बात को खारिज किया है। उनका कहना है कि महिला ने आत्महत्या की इजाजत मांगी ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि शोभा ने सीएम हेल्पलाइन के मामले में थाने द्वारा दबाव बनाने की शिकायत की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी नौगांव को जांच का आदेश दिया गया है। हालांकि, महिला के आवेदन में साफ लिखा था कि वह 卐परेशान होकर आत्महत्या की अनुमति卐 मांग रही है। इस घटना ने प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पुलिस के रवैये से परेशान आम नागरिक के लिए न्याय पाना इतना कठिन है?

पाकिस्तान की अदालत ने दंगों को लेकर पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी पर तय किए आरोप

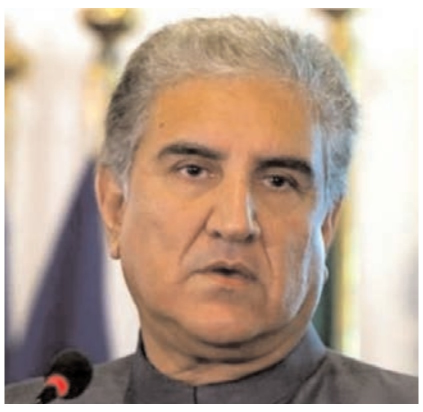

इण्टरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और 20 अन्य लोगों के खिलाफ नौ मई 2023 के दंगों के संबंध में आरोप तय कर दिए हैं। अदालत के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उपाध्यक्ष कुरैशी ने सोमवार को कोट लखपत जेल में सुनवाई के दौरान तय किए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ये मामले PTI नेतृत्व को दबाने के लिए गढ़े गए हैं।

जिन वरिष्ठ नेताओं पर आरोप तय किए गए हैं उनमें PTI की पंजाब इकाई के अध्यक्ष यास्मीन रशीद, सीनेटर एजाज चौधरी, पंजाब के पूर्व राज्यपाल उमर सरफराज चीमा, पूर्व प्रांतीय मंत्री मियां महमूदुर राशिद, पूर्व सांसद आलिया हमजा, रूबीना जमील तथा सोशल मीडिया कार्यकर्ता सनम जावेद शामिल हैं। सुनवाई की अध्यक्षता आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश मंज़र अली खान ने की। एक विशेष अभियोजक ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें थाने पर हमला करने, सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाने और कानून प्रवर्तन कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार जैसे आरोप शामिल थे। अदालत के अधिकारी के मुताबिक, सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के पास अपने दावों को पुष्ट करने के लिए सबूतों का अभाव है। अदालत ने अभियोजन पक्ष को 25 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान अपने गवाह पेश करने का निर्देश दिया।

नौ मई 2023 को खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन्ना हाउस (लाहौर कोर कमांडर हाउस), मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में आईएसआई भवन समेत एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर भी पहली बार भीड़ ने हमला किया। पत्रकारों से बात करते हुए कुरैशी ने खान के प्रति अपनी निष्ठा जतायी। खान अगस्त 2023 से 200 से अधिक मामलों को लेकर जेल में बंद हैं। कुरैशी ने इन मामलों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि इन्हें पीटीआई नेतृत्व को दबाने और उन्हें अवैध रूप से जेल में रखने के लिए गढ़े गए हैं। कुरैशी ने पीटीआई कार्यकर्ताओं और समर्थकों से 24 नवंबर को इस्लामाबाद में प्रस्तावित विरोध मार्च में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह रैली राजनीतिक कैदियों की आजादी, स्वतंत्र न्यायपालिका की बहाली और इमरान खान की रिहाई के लिए है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569